सत्र-04(भाग-2) **24मार्च, 2026**

खण्ड- 08 .... मंगलवार, ...

अंक- 24 03 चैत्र,1948(शक्)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08 सत्र-04(भाग-2) में अंक 23 से 26 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-04(भाग-2) मंगलवार, 24मार्च,2026/03 चैत्र,1948(शक्)अंक-24

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	6
3.	वार्षिक बजट(2026-27)	7-32
4.	अनुपूरक अनुदान मांगें (2025-26)	33-39
5.	दिल्ली विनियोजन (संख्या -2) विधेयक 2026	40-42

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-04(भाग-2) मंगलवार, 24मार्च,2026/03 चैत्र,1948(शक्)अंक-24

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

दिनांक 24.03.2026 को सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्रं.सं.	सदस्य का नाम	क्रं.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	26.	श्री पंकज कुमार सिंह
2.	श्री अभय कुमार वर्मा	27.	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत
3.	श्री अजय कुमार महावर	28.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
4.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	29.	श्रीमती पूनम शर्मा
5.	श्री आशीष सूद	30.	श्री राज करन खत्री
6.	श्री अशोक गोयल	31.	श्री राज कुमार भाटिया
7.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	32.	श्री राज कुमार चौहान
8.	डॉ. अनिल गोयल	33.	श्री रवि कान्त
9.	श्री गजेन्द्र दराल	34.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
10.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	35.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
11.	श्री हरीश खुराना	36.	श्रीमती रेखा गुप्ता
12.	श्री जितेन्द्र महाजन	37.	श्री संदीप सहरावत
13.	श्री कैलाश गहलोत	38.	श्री संजय गोयल
14.	श्री कैलाश गंगवाल	39.	श्री सतीश उपाध्याय
15.	श्री कपिल मिश्रा	40.	श्रीमती शिखा रॉय
16.	श्री करनैल सिंह	41.	श्री श्याम शर्मा

17.	**श्री करतार सिंह तंवर**	**42.**	**श्री सूर्य प्रकाश खत्री**
18.	**श्री कुलदीप सोलंकी**	**43.**	**श्री तरविन्दर सिंह मारवाह**
19.	**श्री कुलवन्त राणा**	**44.**	**श्री तिलक राम गुप्ता**
20.	**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा**	**45.**	**श्री उमंग बजाज**
21.	**श्री मनोज कुमार शौकीन**	**46.**	**श्री विजेन्द्र गुप्ता**
22.	**श्री मोहन सिंह बिष्ट**		
23.	**श्रीमती नीलम पहलवान**		
24.	**श्री नीरज बैसोया**		
25.	**श्री ओम प्रकाश शर्मा**		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र 04(भाग-2) मंगलवार, 24 मार्च, 2026/03 चैत्र 1948 (शक)

सदन पूर्वाह्न 11.08 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जी बैठिए, सभी को प्रणाम। आज एक मिनट इससे पहले कि मुख्यमंत्री जी बजट का प्रस्तुतीकरण करें। हमारे माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार शौकीन का कल जन्मदिन था। तो बिलेटेड मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण, मैं विपक्ष के नेता और सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वह सदन की गरिमा को बना के रखें और सदन में आएं। एक महत्वपूर्ण क्षण होता है बजट जिसमें वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं का भी लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है और यह भविष्य की योजनाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, पूरे दिल्ली के लगभग 2 करोड़ नागरिकों से यह सीधा जुड़ा हुआ बजट है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट से दिल्ली के लोग लाभान्वित होंगे। विपक्ष बजट की कारवाई से अगर अपने को अलग रख रहा है और वह भी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाकर। अभी मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है आतिशी जी का, मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण में डिसरप्शन की, जोकि एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जोकि एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक असंवैधानिक कार्य किया गया जिसमें माफी का स्पेस बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी जो पनिशमेंट थी वह मिनिमाइज रखी, लेकिन उसके बाद वो आने के बाद फिर उन्होंने उसी तरह से सदन की कार्रवाई को बाधा पहुंचाई और जिसके कारण सदन को यह कदम उठाना पड़ा और सत्र के लिए निलंबित किया गया। सत्र प्रोरोग नहीं हुआ था इसलिए वह नहीं आ सके। मुझे नेता, विपक्ष और विपक्ष के सदस्य शनिवार को मुख्यमंत्री जी शुक्रवार को और मंत्री जी शुक्रवार को मिले थे। बजट के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि 24 को वो बजट पेश करेंगी, लेकिन विपक्ष के नेता ने मुझे संपर्क किया शाम को 7:00 बजे 6 बजे के बाद शुक्रवार को शनिवार और इतवार की छुट्टी थी। मुझे लगा कि विपक्ष से मिलना भी उतना ही आवश्यक और जरूरी है। मैंने सचिव महोदय को फोन लगाया और मैंने कहा कि कल

दफ्तर खुलवाइए और विपक्ष का डेलीगेशन मिलना चाहता है, तो मैं उनसे मिलूंगा। विपक्ष से मिलने के लिए दफ्तर स्पेशली खोला गया । विपक्षी नेता विपक्ष के सदस्यों के साथ मेरे कक्ष में आयीं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। जो पत्र मुझे सौंपा गया उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई थी उसकी मैं निंदा करता हूं। वो अगर चेयर के ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इन सदस्यों की जो सस्पेंशन है उसको रिवोक कर दीजिए। मैंने उनको कहा कि आप जब सदन में आएंगी 23 तारीख को तो आप सदन में यह विषय रख दीजिए और जैसा मौका होगा वैसा निर्णय हो जाएगा। उनको एक प्रकार से आश्वस्त करके भेजा, क्योंकि फैसला तो सदन में ही होगा। यह ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिवोकेशन है वो सदन के बाहर होगा। अगर सस्पेंशन सदन में हुआ है तो रिवोक भी सदन में ही होगा, लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि वो सदन में नहीं आए। बाहर हंगामा किया, मिसगाइड किया, गुमराह करने वाले बयान दिए गए और आज फिर मैं उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि वह सदन में आएं, कार्यवाही का हिस्सा बनें, अपना पक्ष रखें, बजट पर अपना पक्ष रखें और जो भी विषय उनको रखना है वह सदन में रखें। सदन उस पर निर्णय लेगा, लेकिन धमकियों से सदन नहीं चलेगा। यह सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा विषय है। इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। धन्यवाद।

अब आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करें उससे पहले मैं उनको बधाई देता हूं कि वह सफलता पूर्वक अपना दूसरा बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना बजट प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

<u>वार्षिक बजट(2026-27)</u>

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष बहुत ही विनम्रता के साथ और कर्तव्य की गहरी भावना के साथ वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के लिए खड़ी हूं और कहना चाहती हूं कि हमारा यह शहर दिल्ली इसकी एक अलग पहचान है, जैसे हर राज्य की एक अपनी पहचान होती है। दिल्ली की एक अपनी पहचान है और वो है इसकी सृजन शक्ति कि कैसे बार-बार गिर के इस शहर ने उठना सीखा। कैसे निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए यह शहर आगे बढ़ा। और मैं यह मानती हूं इसमें जो कृपा है जो आशीर्वाद है वह हमारे इस शहर में जो मां दुर्गा का आशीर्वाद, जो मां झंडे वाली का आशीर्वाद, मां कालका देवी का आशीर्वाद, मां कात्यायनी का आशीर्वाद, मां संतोषी माता का आशीर्वाद और मां योग माया जैसी देवियों के आशीर्वाद से ये शहर लगातार फल फूल रहा है। देश की राजधानी अपनी गरिमा बनाने में सदैव कामयाब रही है। जबकि बीते वर्षों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार छोटी मानसिकता, वोट बैंक की मानसिकता वाले लोग यहां शासन कर रहे थे और उस समय दिल्ली ने बुरा दौर भी देखा। परंतु दिल्ली आज एक निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जहां नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं अध्यक्ष जी, बल्कि धरातल पर परिणाम देती हैं। जहां शासन केवल व्यवस्था में नहीं

है बल्कि विश्वास का माध्यम बनता है। जहां विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन में दिखाई देता है। आज दिल्ली ट्रिपल इंजन की गति के साथ में आगे बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। कल हमने सदन पटल पर इकोनॉमिक सर्वे रखा था और इकोनॉमिक सर्वे यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में उद्यमशील नागरिक और वाइब्रेंट इकोनॉमी के बल पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज विकास किया है। परंतु बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और freebies जैसी संस्कृतियां जिसकी सरकारों की जो प्राथमिकता रही उसके कारण से वर्ष 2021-22, 2023-24 और 2024-25 में विकास दर प्रभावित रही। इस बीच बहुत सारे दिल्ली के उद्यमी स्टार्टअप से जुड़े लोग हाई स्किल मैन पावर दिल्ली से दूर हुई और इसी कारण से 2018 से लेकर 2024 के बीच अपने राजस्व में गिरावट भी आई। प्रति व्यक्ति आय इन वर्षों में जिनका जिक्र मैंने किया राष्ट्रीय औसत के मुकाबले स्थिर रही लगभग और दिल्ली का जीएसडीपी 2024-25 में 8.9% की वृद्धि के साथ 12.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025-26 में यह 9.4 की दर से बढ़कर के 13.27 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। यह हमारे नेतृत्व का प्रभाव है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से दिल्ली में चल रही सभी परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली की भागीदारी वर्ष 2024-25 में 3.67% से बढ़कर 2025-26 में 3.72% होने का अनुमान है। यह भी बढ़ोतरी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और वर्ष 2025-26 में यह 5.3 लाख तक जाने की संभावना है। आज दिल्ली राज्य की पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 25-26 के Revise Budget Estimate में 99 हजार 310 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखती हूं। इसमें से 66 हजार 710 करोड़ Revenue Expenditure के लिए और 32 हजार 600 करोड़ Capital Expenditure के लिए प्रस्तावित है। यह पिछला बता रही हूं भाई अभी। 41 हजार 500 करोड़ और 57 हजार 810 करोड़ क्रमशः Establishment & other Committed Expenditure तथा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए Revised Estimate में प्रस्तावित है। महोदय वर्ष 25-26 के संशोधित अनुमानों के अंतर्गत द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान हेतु 6 हजार 514.58 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि उक्त पूरक अनुदान की मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए आप सबको ध्यान है हमने एक लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया था और एक दशक तक दिल्ली में लगातार जो Capital Expenditure है, जो दिल्ली के infrastructure में खर्च होता है, दिल्ली की development में खर्च होता है वो मात्र 7 हजार करोड़ से 15 हजार करोड़ के दायरे में सीमित रहा वर्षों तक और यह कभी भी इस शहर के लिए पर्याप्त नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हमने इस ट्रेंड को तोड़ा और 2025-26 में Capital Expenditure का आवंटन हमने बढ़ाकर 28 हजार 115 करोड़ किया था जो कि वर्ष 24-25 के मुकाबले वर्ष 24-25 में था 11 हजार 485 करोड़, हमने 25-26 में 28 हजार 115 करोड़ किया। ये 145% का इजाफा था, ऐतिहासिक छलांग थी जो Capital Expenditure की दृष्टि से हमने किया और यह परिवर्तन यह परिवर्तन दिल्ली के लिए जो हो पाया उसका कारण, उसका कारण केवल और केवल दिल्ली में हमें

केंद्र सरकार के माध्यम से जो सहयोग मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व मिला, जो आदरणीय गृह मंत्री जी का साथ मिला, इस सबके कारण आज दिल्ली केंद्र की इस हैंड होल्डिंग के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है और आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूं वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान और आपको यह जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1 लाख 3 हजार 700 करोड़ का budget estimate प्रस्तुत करती हूं, ₹1 लाख 3 हजार 700 करोड़, पिछली बार से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है और इसका वित्त पोषण इसका वित्त पोषण माननीय अध्यक्ष जी 74 हजार करोड़ रूपये टैक्स रेवेन्यू से होगा, ₹900 करोड़ non tax revenue से होगा, 3931 करोड़ रूपये centrally sponsored schemes के माध्यम से होगा और 591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से होगा और हम इस वर्ष 16 हजार 700 करोड़ रूपये बाजार से ऋण लेंगे वह भी बहुत ही कम ब्याज दर पर और ₹2570 करोड़ केंद्रीय अनुदान के माध्यम से होगा और SASCI योजना के तहत ₹ ढाई हजार करोड़ हमें केंद्र से मिलने की आशा है और बाकी की शेष राशि opening balance और अन्य capital revenue से आएगी और इस बजट में भी हमने 70.3% Revenue Expenditure के लिए रखा है और 29.7% Capital Expenditure के इसमें आवंटित किया है जो पिछले साल से भी ज्यादा Capital Expenditure इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और GSDP ratio 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज्यादा है और इसी के साथ दिल्ली revenue surplus दिल्ली में revenue surplus 9092 करोड़ रूपये का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पर कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने green budget के रूप में प्रस्तुत किया है, green budget के रूप में और हर योजना को हमने green lens से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा 21% हिस्सा green budget के लिए आवंटित किया है इस बार, जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, यह जो पूरा बजट मैं प्रस्तुत करने वाली हूं, मैंने इसमें 10 focus area रखे हैं जिसका ब्यौरा मैं sector-wise आपके सामने रखना चाहूंगी।सबसे पहले infrastructure, मजबूत बुनियाद ही तेज विकास की नींव है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा infrastructure का जो मंत्र दिया है वो फोर एस, चार प्रकार के एस की बात उन्होंने की है scope, scale, speed और skill। इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प किया जहां इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकास गाथा एक साथ सांस लेंगी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे सभी निकाय मिलकर के दिल्ली में बहुत ही तेजी के साथ विकास की गति बढ़ाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाकर के दिल्ली के लिए काम किया जाएगा। दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली, दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार इतिहास में MCD को दिल्ली सरकार

द्वारा 11 हजार 666 करोड़ रूपये देने का प्रावधान हमने किया है जो आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है और इसी तरीके से NDMC और Delhi Cantonment Board के लिए भी हमने 146 करोड़ रूपये वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है। सभी एजेंसीज काम करेंगी तो यह triple engine, ट्रिपल गति के द्वारा दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली शहर कई संस्कृतियों का और शहरों का melting point है जहां एक और करोल बाग की, सदर बाजार की चहलपहल यह शहर रोजाना देखता है तो दूसरी ओर, दूसरी ओर बारा खंभा की गगनचुंबी इमारतों को हमारा रोजाना का ध्यान जाता है। हमारा लक्ष्य है flawless connectivity, climate, corridors और तकनीकी रूप से सुरक्षित सड़कें। मैं दिल्ली के infrastructure के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में PWD विभाग के लिए ₹5921 करोड़ ₹5921 करोड़ और शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए 7887 करोड़ रूपये का बजट का प्रस्ताव करती हूं। महोदय दिल्ली का विकास यमुना पार के विकास के बिना असंभव है। पिछली सरकारों ने यमुना पार, पिछली सरकारों ने यमुना पार के विकास की अनदेखी की। हमने वर्ष 25-26 में ट्रांस यमुना development board को फिर से क्रियाशील किया और 26-27 में यमुना पार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए हमने ₹300 करोड़ का बजट पहले फेज में रखा है और यमुना पार में वहां की सड़कें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो इसका प्रयास किया है और इसी प्रकार, इसी प्रकार अनाधिकृत कॉलोनियां जो हमेशा से उपेक्षा की शिकार रही। इस अनाधिकृत कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, ड्रेनेज के लिए, लाइटों के लिए हमने 800 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है। दिल्ली केवल मेट्रो का मेट्रो शहर नहीं है अध्यक्ष जी। इनकी आत्मा गांव में बसती है और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए हमने 787 करोड़ रूपये का आवंटन का प्रस्ताव दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए किया है। दिल्ली केवल ऊपरी तौर पर विकसित नहीं बल्कि भीतर से मजबूत होनी चाहिए। दिल्ली का हर कोना विकसित होना चाहिए। इसलिए हमने हर सेक्टर के लिए यहां पर बजट का प्रावधान किया है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी हमने 960 करोड़ रूपये का आवंटन का प्रस्ताव मैं आज इस हाउस के समक्ष करना चाहती हूं। दिल्ली में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए डस्ट फ्री करने के लिए पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली में हमारी सड़कें हैं 1400 कि.मी. की सड़कें जिसमें से 400 कि.मी. पिछले साल हमने बनाई थी और इस साल हमने टारगेट लिया है साढे सात सौ कि.मी. सड़कों को एंड टू एंड कारपेटिंग करने का ताकि दिल्ली की सड़कें डस्ट फ्री हो, धूल ना उड़े और इसके लिए हम 1392 करोड़ रूपये का प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। एमसीडी को जो फंड मैंने पहले बताया है उसके अलावा 1000 करोड़ अलग से सड़कों के विकास के लिए दिया जाएगा। हमने इंडस्ट्रियल एरिया में चाहे वह नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया है या नॉन कंफर्मिंग दोनों प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए इस साल पहली बार 160 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव किया है। दोनों क्षेत्रों में पहली बार किसी सरकार ने नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने की पहल की है और इतना बड़ा बजट रखा गया है। दिल्ली में हमने देखा जगह-जगह पे फुटओवर ब्रिज की जरूरत दिखाई देती है। बहुत सारे फुटओवर ब्रिज इस साल भी हमने शुरू किए हैं। परंतु अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 25 करोड़ रूपये रखे

हैं दिल्ली में अलग-अलग जगह पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए। अनेकों योजनाएं जिस पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। आपको ध्यान होगा बारापुला का कॉरिडोर पिछली सरकार के समय में 2016 से शुरू हुआ पर 2025 तक भी पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो आम आदमी पार्टी की। पर हमने हमारी सरकार ने आने के बाद इस बारापुला कॉरिडोर पे काम किया। इसकी पुरानी जो परमिशंस अटकी हुई थी, जो लैंड एक्वायर करनी थी, वह सारे काम किए। इसमें 1650 करोड़ रूपये के इस प्रोजेक्ट में जो गैप फंडिंग है इस साल हम 210 करोड़ रूपये इसमें दे करके जून तक जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिल्ली की जनता को सौंपने वाले हैं। कालका जी तक मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को भी हमने मंजूरी दी है और इसकी लागत 371 करोड़ रूपये है जिसमें 150 करोड़ रूपये का प्रावधान इस साल किया है। यह साउथ दिल्ली वाले कौन है भाई? तो ताली कम आ रही है। इसके अतिरिक्त मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ रूपये की कुल लागत वाली परियोजना को भी हमने स्वीकृति दी है। नजफगढ नाला जो दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है। उसके दोनों तरफ दोनों तरफ दो-दो लेन की सड़क बनाने के लिए हमने 454 करोड़ रूपये इस साल के बजट में दिए हैं ताकि दिल्ली की कनेक्टिविटी दिल्ली में डस्ट फ्री माहौल एक बहुत बड़ी यह अचीवमेंट रहेगी और बहुत सारे उससे जुड़े हुए गांव देहातों को एरिया को इससे लाभ मिलने वाला है। साथ में अध्यक्ष जी, बहुत समय से लंबित निम्नलिखित प्रोजेक्ट को भी मैं हमारी सरकार पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगी आजादपुर से त्रिपोलिया गेट इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर घंटाघर स्टेशन से इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम यमुना विहार से भजनपुरा इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम साकेत जी मेट्रो स्टेशन से छह लेन का अंडरपास एमबी रोड से एलबीएस मार्ग तक दो लेन का अंडरपास का काम लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से एमबी रोड तक फ्लाईओवर तक दो लेन का एलिवेटेड रैंप बनाने का काम एशियन मार्केट बतरा अस्पताल तक छह लेन का एकीकृत फ्लाई ओवर डबल डेकर सिस्टम के साथ बनाने का काम, मां आनंदमई तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी तक छह लेन का एकीकृत फ्लाई ओवर बनाने का काम यह सारे प्रोजेक्ट जो कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा के लागत के प्रोजेक्ट है। इस वर्ष हमने बजट 26-27 में अध्यक्ष जी इसके इसके लिए 575 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए हैं ताकि यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से ना केवल दिल्ली का कंजशन दूर होगा बल्कि प्रदूषण में भी बहुत कमी आएगी। जाम भी यहां पे हमें मुक्ति मिल पाएगी। सभी एमएऐज को अपने एरिया में अलग से डेवलपमेंट करने के लिए टोटल साढे तीन सौ करोड़ रूपये का बजट भी रखा गया है और जो फंड पिछली बार आप लोगों को मिला वैसे ही और फंड आपको मिलता रहेगा। अध्यक्ष जी, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। एक स्वच्छ हरित सशक्त दिल्ली। केवल वायदा नहीं। यह केवल वायदा नहीं मोदी जी की गारंटी है कि देश की राजधानी, देश की राजधानी ईंट और पत्थरों से नहीं अवसरों के आंगन से बनेगी और यह दिल्ली दिल्ली उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी दिल्ली में जितनी मंडियां हैं। वर्षों से बुरी हालत में पड़ी है। इन मंडियों में हमने टिकरी टिकरी खानपुर और गाजीपुर मंडियों के विकास के लिए विकास किया जाएगा जो किसानों के लिए व्यापारियों के सपने सच करने जैसा होगा। जहां किसान का पसीना समृद्धि में बदल पाएगा। मैं ऐसे मौके पर यह भी जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं,

जितने भी हमारे ऑफिसिसेस हैं, अधिकतर किराए के भवनों में चल रहे हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे अधिकारी जिन प्रिमिसेस में रहते हैं, वो वर्षों पुराने हैं। जर्जर अवस्था में हैं। आज सरकार ऐसी स्थिति में चल रही है जिसकी ओर कभी किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले मुख्यमंत्री, पिछले मंत्री अपने लिए तो शीश महल बनवाते थे। पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छे घर हो यह कभी उनकी चिंता नहीं रही। इस बार इस बार दिल्ली सरकार अपने कार्यक्रमों में, अपनी योजनाओं में एक तो दिल्ली का बड़ा इंटीग्रेटेड नया सचिवालय बनाने का काम करेगी। अधिकारियों के लिए कर्मचारियों के लिए नई रेजिडेंशियल कॉलोनी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगी और इसी तरीके से जिस भी जितने हमारे विभाग हैं जितने मंत्रालय हैं इन सबको बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार अपने इस साल के इस साल के प्रोजेक्ट में उन सबको हम लेने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को sustainable और फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में हमने डीडीए के साथ मिलकर के यमुना पेरीफरी पेरिफेरल वे में साइकिल ट्रैक विकसित करने का काम शुरू किया है। उसकी योजना को पूरा कर लिया है। जितनी दिल्ली में ड्रेंस हैं, बड़ी ड्रेंस हैं, उसमें सरकार का ये सोचना है कि हम उन ड्रेंस के ऊपर सोलर पैनल लगाएं और सोलर पैनल्स के माध्यम से दिल्ली में क्लीन एनर्जी जनरेशन को संभव करें। तो इस श्रृंखला में इस बार सरकार आगे बढ़ेगी और इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करते हुए हम दिल्ली को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे अध्यक्ष जी। हमने एमसीडी के साथ मिलकर के दिल्ली में पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए कई नई पार्किंग्स पे काम शुरू किया है और इस साल उस श्रृंखला में मुझे लगता है कि कई पार्किंग्स को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको फंड भी देंगे। मैं बात करना चाहूंगी बिजली विभाग की और अध्यक्ष महोदय हमारा टारगेट है दिल्ली को अनडिस्टर्बड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए और इसके लिए हमने पावर डिपार्टमेंट को ₹3942 करोड़ का बजट देकर के दिल्ली में बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सौर ऊर्जा के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी दिल्ली सरकार में लगातार चलेगी जिससे हम अपनी पावर इंडिपेंडेंस को कायम कर सकें, इसको आगे बढ़ा सके। दिल्ली अब सौर ऊर्जा की तरफ तेज गति से बढ़ेगी और काम करेगी। अध्यक्ष जी एक बड़े मशहूर शायर ने एक बात कही कि:

''दिल्ली कहां गई तेरे कूचों की रौनक,

कि दिल्ली कहां गई तेरे कूचों की रौनक

गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं।''

हम जहां जाते हैं हम देखते हैं तारें ही तारें, तारें ही तारें और जो हादसों का भी कारण बनती हैं घरों से लोग आसमान तक भी नहीं देख पाते। हमने इस फाइनशियल ईयर में दिल्ली में वायरिंग को अंडरग्राउंड करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए और उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने चांदनी चौक में शुरू किया जो कि 160 करोड़ की लागत से था। जहां 52 किलोमीटर लंबी ओवरहेड बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया गया, किया जा रहा है। यह अपने आप में दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक, चौक क्षेत्र के लिए बहुत ही, बहुत ही सुंदर कार्य शुरू हुआ है। मैं बहुत-बहुत बधाई

देती हूं अपने बिजली विभाग को और इस बार हमने ₹200 करोड़ का फंड और दिया है। इसी प्रकार के काम को करने के लिए और दिल्ली की सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुरक्षा भी मिलेगी, दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा और दिल्ली की सुंदरता भी बढ़ेगी और दिल्ली भविष्य में बिजली की खपत के अनुमान को ध्यान में रखते हुए लगातार नए सबस्टेशन भी बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स भी लगा रहे हैं ताकि दिल्ली की जो पावर कंजमशन है लगातार ठीक-ठाक सप्लाई के साथ चलती रहे। अध्यक्ष जी एक घटना हम सबको बड़ी तकलीफ हुई उसके साथ में जो पीछे फायर का इंसिडेंस पिछले दिनों हुआ। दिल्ली में हम सब देखते हैं कि बहुत ही संकरी गलियां हैं। अनप्लांड कॉलोनियां बसी हुई है। झुग्गियां, अनअथोराइज्ड कॉलोनी, सिंगल एंट्री हाउसहोल्ड यानी कि हमारे फ्लैट हमारे कई-कई मंजिलों के मकान जहां पे एक दरवाजा होता है। अगर नीचे से आग चढ़ना शुरू हो तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये कहानी उन फ्लैटों की भी है, ये कहानी उन कोठियों की भी है और झुग्गी-बस्तियां जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया में हैं, जहां अनअथोराइज्ड कॉलोनियां हैं, जहां कोई नक्शे नहीं पास होते, जहां पे चौड़ी सड़के नहीं है, जहां पे कोई फायरटेंडर जाने की जगह नहीं है, ऐसी विकट परिस्थितियों में दिल्ली लगातार चल रही है। इसलिए हमें अपने फायर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है। वर्ष 2025-26 में हमने इस दिशा में बहुत ईमानदार प्रयास किए। 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल हमने लिए। अत्याधुनिक मशीनें फायर सर्विसिज से जोड़ी और इस साल 26-27 में भी फायर डिपार्टमेंट को हमने पिछले साल जो फंड दिया था ₹530 करोड़ उसके उसे बढ़ा करके हमने ₹674 करोड़ करने का प्रस्ताव किया और इसके अंतर्गत नए फायर सर्विस स्टेशन, 26 क्यूआरवीस, आधुनिक मशीनरीज और अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था की जाएगी जो जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष जी दिल्ली में हमेशा जो सबसे बड़ी समस्या एक मध्यम वर्गीय परिवार को हो, कोठी वाला हो, झुग्गी वाला हो, हर एक को रहती है वो है सीवर और पानी। सीवर, पानी, स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन ये सब जुड़ा हुआ है। और इसके लिए पिछले सरकार जब हमें दिल्ली का काम की जिम्मेवारी मिली। हमने पिछले साल भी 9000 करोड़ का बजट इस विभाग को दिया था और बहुत ही तीव्र गति से दिल्ली में नई पानी की लाइनें डलने का काम हो या सीवर की लाइनें डलने का काम हो वो लगातार किया गया। जल और सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना। सेवा के वितरण को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की लगातार कोशिशें की गई। इस साल मैं कहना चाहती हूं कि हम इस बजट को इसी प्रकार बना के रखेंगे। ₹9000 करोड़ इस साल भी हम अपने दिल्ली जल बोर्ड को दे रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट पिछले साल हमने शुरू किए जैसे रजोकरी, बिजवासन, सिरसपुर और पल्ला में नए भूमिगत जलाशयों का संचालन और द्वारका में 50 एमजीडी जल संशोधन संयंत्र की तीव्र गति से निर्माण ये दिल्ली के लिए अमृत धाराएं साबित होंगी। अध्यक्ष जी हमने पिछले साल 172 किलोमीटर की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइनें बिछाई। हमने 13 किलोमीटर लगभग ट्रांसमिशन लाइनें लगाई। जल आपूर्ति में हमने 10 एमजीडी की वृद्धि की और आगे भी 36 एमजीडी के अतिरिक्त जल का हमने लक्ष्य लिया हुआ है। ये सब कुछ मिलकर के दिल्ली में जल संतुलन को दृढ़ करेंगे। हम नॉन रेवेन्यू जल को भी 45% से घटाकर 15% करने का हमारा लक्ष्य है। हर दिल्ली के हर घर में नल के माध्यम से जल जाए ये हमारी दूर दृष्टि है। किसी को भी इस टेंपरेरी टैंकर की व्यवस्था से पानी ना

लेना पड़े। और इसके लिए हमने चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसमें पाइप लाइन के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। जिसमें लगभग नौ विधानसभाओं को लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए यानी चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमने 475 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उसमें भी 10 विधानसभाओं को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। हम एडीबी बैंक से उसके वित्त पोषण की व्यवस्थाओं करने के लिए प्रस्ताव हमने एडीबी बैंक के पास भेजा है। हम दिल्ली में सीवेज सिस्टम को बेहतर करते हुए जो हमारा टारगेट है कि अभी दिल्ली की जो कैपेसिटी है लगभग 707 एमजीडी पानी को ट्रीट करने की है। हम चाहते हैं इस कैपेसिटी को हम 1500 एमजीडी पे लेके जाएं। सारी सीवर लाइनें, सारी जितने एसटीपी हैं उन सबको बेहतर करने का हमारा टारगेट है। और इस साल भी हमने 180 कि.मी. नई सीवर लाइन बिछाई और 110 कि.मी. सीवर लाइनों को इस साल बदला गया है। 35 डीसेंट्रलाइज प्लांट को स्वीकृत किया गया है। 10 नए एसटीपी प्लांट्स का अलग से प्रस्ताव रखा गया है। सीवर लाइन की कमी के कारण बहुत सारे एरिया सीवर ओवरफ्लो होता है। कहीं गंदगी सड़कों पर बहती है, किराड़ी जैसे घटनाएं हम लगातार देखते हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने सीवर के लिए एसटीपी के लिए पानी की लाइनों के लिए कभी काम ही नहीं किया। परंतु हमारी सरकार लगातार जनता के हित में इन सब कामों को लगातार कर रही है। स्पीड में कर रही है और बहुत बड़ा बदलाव रोजाना दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को यहां देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष जी मैं जरूर एक और दिक्कत जो दिल्ली की है उसका जिक्र करना चाहूंगी। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग जब भी बारिश का मौसम आता है बातें होती हैं, टीवी पर फोटो चलती है, अखबार में फोटो छपती है पर समाधान क्या हो कभी इसने, इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया। पहली बार 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे मंत्री जी ने, हमारे विभाग ने इस पे डिटेल्ड स्टडी करके 50 साल बाद दिल्ली में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लेके आया गया। और, और उस ड्रेनेज मास्टर प्लान की सिफारिशें लागू की गई जिसके अंतर्गत हमने एमबी रोड की ड्रेनेज को मंजूरी दी। हमने किराड़ी, मुंडका, बवाना, नांगलोई विधानसभा से जल निकासी की समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे लाइन के समांतर वहां पे बड़ी ड्रेन 221 करोड़ की लागत से उसको बनाने की मंजूरी दी। एमबी रोड वाली ड्रेन 387 करोड़ की लागत से बननी है। और इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में अलग-अलग जगहों पे हमारे फ्लड एवं इरीगेशन विभाग द्वारा ये ड्रेंस को नई बनाने का काम, पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है और इस फंड, इस मद में हमने अलग से 610 करोड़ रूपये का फंड हमारे सिंचाई विभाग को दिया है।

एक और अच्छा काम इस बीच में हमारे सिंचाई विभाग द्वारा किया गया, हमारी अन्य-अन्य एजेंसियों ने किया, वो है डीसिल्टिंग। नालों की डीसिल्टिंग पहली बार दिल्ली में इस स्तर पर जाके हुई कि दिल्ली में यमुना जी पे 207 का लेवल आ गया पानी का, फिर भी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई, फिर भी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। उस लेवल पर भी हमने दिल्ली को बचा के रखा क्योंकि लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद पहले से ही यमुना से, हमारे ड्रेन से निकाली जा चुकी थी और इस ऐतिहासिक जलस्तर 207.48 मीटर पे पानी आ गया। वो निशान हर बार हम टीवी में देखते थे। पानी

यहां आने वाला है, आने वाला है, पर इस बार दिल्ली में पानी नहीं भरा। यह डिसिल्टिंग का कमाल था कि ऐतिहासिक जगह जहां हर साल पानी भरता था इस बार नहीं भरा और आने वाले इस साल में भी दिल्ली में जल भराव ना हो इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है।

हमने फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बनाने का काम शुरू किया है जो कि 50 करोड़ की लागत की है। इस तरीके से दिल्ली में पानी की, सीवर की, ड्रेनेज की, ये सारे काम सरकार के लिए प्रायोरिटी है और सरकार इस पर काम कर रही है।

मैं अगले सेक्टर में बताना चाहूंगी हेल्थ केयर के बारे में। सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। अध्यक्ष जी हम शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी वेलफेयर स्टेट के केंद्र बिंदु होते हैं। यही विचार हमारी नीतियों में भी है। हमारी सरकार प्राइमरी से लेकर के इंटेंसिव केयर तक एक मजबूत, सुलभ, किफायती व्यवस्था गढ़ रही है। और हमारा यह मानना है कि जो उपचार है वो अधिकार है, उपकार नहीं है, उपकार नहीं है। इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया है, 12,645 करोड़ रूपये का। और जितने पुराने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हॉस्पिटल थे, आज ये आए नहीं हैं विपक्ष वाले, आते तो मैं इनको, भाषण देने में मजा भी नहीं आ रहा,.. वो सुन ही नहीं सकते, ऐसे-ऐसे काम करके गए हैं कि जब वो फाइलें खुलती हैं तो यह एहसास होता था कि करते क्या थे और सिस्टम में इतना ज्यादा गड़बड़, इतना करप्शन। इनको तो, 11 साल भी इनको काम करने का मौका कैसे मिला? पहले दिन ही, पहले दिन से ही यह पकड़ में आने वाले काम इन्होंने किए। हमने मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल, ज्वालापुरी में उन अस्पतालों को पूरा करने के लिए इस साल 515 करोड़ रूपये का फंड रखा है। जबकि राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, बाबासाहेब अंबेडकर हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में शासकीय की योजना के तहत केंद्र के द्वारा पोषित साक्षी योजना, शासकीय योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर हम करेंगे। और साथ ही अधूरे पड़े हुए लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का निर्माण कार्य भी इस साल पूरा किया जाएगा। हमने जो सात आईसीयू अस्पताल पिछली सरकार अधूरे छोड़ के भाग गई थी उसको पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ रूपये का फंड इस वर्ष हमने रखा है। हमने अस्पतालों में मशीनें खरीदने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दवाइयां खरीदने के लिए 787 करोड़ रूपये का फंड अलग से सीपीए के माध्यम से खरीदारी करने के लिए रखा है, 787 करोड़ रूपये।

साथ ही 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' जो पिछले साल हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने लागू की थी, उसमें हमने पहले जो अंतोदय के राशन कार्ड थे उनको शामिल किया था, बाद में हमने उसमें आशा वर्कर जोड़ी, आंगनबाड़ी कर्मी जोड़े, उसके बाद हमने दिल्ली की विधवा बहनों को उस कैटेगरी में जोड़ा, दिव्यांग लोगों को उसमें जोड़ा। और अभी तक साढ़े सात लाख लाभार्थियों पर इस सूची को हमने एक्सटेंड किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक कैटेगरी और इसमें जोड़ना चाहती हूं और वह है दिल्ली राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर लोग उनको भी, उनको भी हम इस सूची में जोड़ेंगे। पिछले दिनों जब मैं इस समुदाय के लोगों से मिली, ट्रांसजेंडर्स से मिली तो उन्होंने

अपनी व्यथा कही कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है इलाज करवाना। हम, हमें किसी सूची में रखा नहीं जाता। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते। इसके लिए हमें प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराना पड़ता है। तो हमने अपनी 'आयुष्मान योजना' की इस कैटेगरी में अब से ट्रांसजेंडर्स को भी जोड़ा है और टोटल 202 करोड़ रूपये का प्रावधान इस योजना के मातहत रखा है।

अध्यक्ष जी, हमने पिछले एक साल में दिल्ली में 370 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' खोले। हर एक की विधानसभा में खुले हैं। सबके यहां खुले हैं ना भई?.. प्राइमरी हेल्थ केयर के ये शानदार सेंटर हैं, अनेकों व्यवस्थाएं हैं। और इस साल वर्ष 2026-27 में हम नए 750 अन्य 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' स्थापित करेंगे जिसके लिए हमने केंद्र की मदद और हमारी स्टेट का पैसा मिलाकर के 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। भई थक गए हो क्या? अभी 25% हुआ है।और दिल्ली में 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज बनाई जाएंगी। दो, नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का प्रावधान भी इस साल हमने किया है। केंद्र की सहायता से श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 200 करोड़ रूपये की लागत से एक नया ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा, इसके लिए मैं केंद्र का धन्यवाद देती हूं।

पिछले वर्ष पहली बार दिल्ली में 'दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी' बनाई गई थी। इससे पहले थी ही नहीं दिल्ली में और अब यह बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इस साल हमने पांच नए 'आयुष सेंटर' भी खोले। इस मद में हमने 60 करोड़ रूपये का आवंटन किया है, 60 करोड़ रूपये का।

दिल्ली में बहुत सारे बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर आज दिल्ली में सीटें बहुत कम हैं। यूजी में 595 सीट हैं और पीजी में 553 सीटें हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम मेडिकल कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ाएंगे, सीटों की भी संख्या बढ़ाएंगे। यूजी में हम इनको लगभग 820 सीटें करने वाले हैं और पीजी में 762 सीटें करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ केंद्र सरकार की मदद से होने वाला है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो लोग पूछते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या लाभ है, तो मैं बताना चाहती हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार का यह लाभ है जो मेरी कही हुई एक-एक बात में यहां दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, हमने इंदिरा गांधी अस्पताल जो द्वारका में है उसमें भी एक नए मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये इस साल के बजट में रखे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी एक बहुत ही विशेष योजना। एक नन्हा बालक जब किसी घर में जन्म लेता है तो वह मात्र कुछ घंटे का भी होता है परंतु हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा हो जाता है। हमारे लिए वो अनमोल हो जाता है पर कई बार क्या होता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसी बीमारियां बचपन से ही जो उसके अंदर होती है पर वो उसी समय नहीं पता चलती। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे वह बड़ा होने लगता है, तब वो बीमारियां ध्यान में आती हैं परंतु तब तक उसका इलाज संभव नहीं होता फिर और वो बच्चा उसी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में पलता है, बढ़ता है और कहीं ना कहीं परिवार पर और मां-बाप पर बोझ बन जाता है। वो बालक जो अनमोल था वो आज तकलीफ का कारण बन जाता है। कोई मां-बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में कोई ऐसी बीमारी पले। हमने दिल्ली सरकार की ओर से एक विशेष योजना लेकर के आए हैं जिसका नाम ही

हमने अनमोल दे दिया है। अनमोल, यानी Advanced New born Monitoring and Optimal Life Care जिसमें सरकार 25 करोड़ रुपये का हमनें इसमें फंड रखा है। मात्र एक खून की बूंद से एक ड्रॉप ब्लड के साथ में 56 प्रकार की टेस्टिंग नवजात शिशु की होगी जो सरकार की ओर से पूरी तरीके से निशुल्क होगी। बाहर यह टेस्ट बहुत महंगा है अध्यक्ष जी परंतु हम दिल्ली का प्रत्येक बालक, दिल्ली का प्रत्येक नवजात शिशु चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, उसको अनमोल के माध्यम से छप्पन टेस्टिंग पूरी तरीके से निशुल्क देंगे यह दिल्ली के बच्चों के लिए उस अनमोल विरासत के लिए हमारी ओर से उपहार है। हम एक और महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। दिल्ली में एक डिजिटल ब्लड बैंक और डोनर्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि कहीं भी किसी भी कोने में ब्लड की जरूरत हो तो उस डिजिटल डायरी के माध्यम से डोनर का और ब्लड यूनिट का पूरा ब्यौरा हमारे दिल्ली के निवासियों को मिल पाएगा। साथ ही हम real time ventilator bed vacancy monitoring system develop करेंगे। कितनी बार हम सब ने देखा है कि एक परिवार अचानक कोई घर में बीमार हो गया, स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया और लेकर दौड़ता है हॉस्पिटल में तो पता चलता है कि वहां तो आईसीयू खाली नहीं है। उसको लेकर फिर दूसरे अस्पताल में जाता है तो पता चलता है वहां आईसीयू खाली नहीं है और ऐसे ही चलते-चलते कई बार वो जीवन खत्म हो जाता है। हम ऐसा real time ventilator करेंगे कि चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो आपको तुरंत यह पता चल जाए की किस अस्पताल में वेंटिलेटर खाली है और व्यक्ति अपना पेशेंट लेकर सीधा वहां जाए।

अध्यक्ष जी, शिक्षा, ज्ञान, कौशल और भविष्य निर्माण शिक्षा के माध्यम से हमनें शिक्षा के लिए इस साल के बजट में 19148 करोड़ रुपये का फंड रखा है। यह खर्चा नहीं है, यह निवेश है। निवेश है हर छात्र, हर शिक्षक उनके सपनों में, उनके सपनों में निवेश है अध्यक्ष जी और हमने पिछली सरकारों ने बातें तो बहुत की स्कूल बिल्डिंग स्कूल पर उन्होंने टॉयलेट को भी गिन लिया कि यह मैंने एक कमरा बना दिया और जबकि हालत यह है सुनके हैरानी होगी आप सबको कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक मेडिकल रूम भी नहीं है। कोई बच्चा बीमार हो जाए तो एक रूम एक्स्ट्रा नहीं होता स्कूलों में की किसी बच्चे को जाकर वहां लिटाया जा सके और दिल्ली में आज भी ऐसे-ऐसे स्कूल हैं। ये हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष जी बैठे हैं मैं हैरान रह गई कह रहे जी एक बिल्डिंग में, एक शिफ्ट में दो स्कूल चलते हैं। तीन दिन एक स्कूल के बच्चे आते हैं और तीन दिन दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं। ऐसा शिक्षा का मॉडल, ऐसा शिक्षा का मॉडल जिसकी दुहाई देते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग। ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं। गांव देहात में नहीं देखा जो देश की राजधानी दिल्ली में इन लोगों ने किया। हमने स्कूलों के भवन निर्माण के लिए इस साल 200 करोड़ रुपये रखे हैं और स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड़ रुपये अलग से रखे हैं तो टोटल स्कूल बिल्डिंग फंड में 475 करोड़ रुपये का यह फंड हमने रखा है। अध्यक्ष जी, एक बहुत ही प्यारी योजना मैं लेकर के आई हूं। एक बहुत ही प्यारी योजना दिल्ली की बेटियों के लिए। मैंने बजट के लिए चर्चा करते हुए अपने दिल्ली सरकार के स्कूल की बेटियों को बुलाया, उनसे चर्चा की। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या कमी है, सब कुछ अच्छा है। सब चीजों की बहुत तारीफ करी कि हां ये भी ठीक है, ये भी ठीक

है, बाकी चीजें ठीक हो रही हैं पर एक चीज जो उन्होंने कही उसको मैंने भी महसूस किया। उन्होंने यह बताया कि दिल्ली सरकार के किसी बच्चे के पास में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। आज भी उसको अपने घर से स्कूल तक जो आना होता है वो प्राइवेट व्हीकल करता है, मां-बाप छोड़ने आते हैं या वो पैदल चलकर आता है और ऐसे में कई बार बेटियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है और कई बार यही दिक्कत उन बेटियों के लिए ड्रॉप आउट का कारण भी बन जाती है। मां-बाप कहते हैं भाई रहने दे आसपास स्कूल नहीं है दूर कहां जाएगी रहने दे तेरे को स्कूल ही नहीं भेजेंगे। पर मैं दिल्ली की उन सभी बेटियों के लिए इस बार अपने फंड, अपने इस बजट में कुछ उपहार लेकर आई हूं। दिल्ली की वो बेटियां जो नौवीं क्लास में आई हैं ऐसी लगभग 130000 बेटियां हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रही हैं। हर उस बेटी को हम एक साइकिल उपहार देंगे। हर बेटी को, नौवीं क्लास की हर बेटी को एक साइकिल उपहार देंगे इसके लिए हमने 90 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अब हमारी बेटी पैदल नहीं जाएगी साइकिल पर अपने स्कूल जाएगी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं चार साल खूब आनंद के साथ वो बच्ची अपने स्कूल अपने व्हीकल से जाएगी उसे किसी का इंतजार नहीं करना। यह योजना पहली बार दिल्ली राज्य में लाई गई है, दिल्ली की बेटियों के लिए लाई गई है। और अब बेटे कहेंगे भाई हमारे लिए क्या, बताना पड़ेगा ना। तो भाई बेटों के लिए कंडीशन है 10वीं क्लास के हमारे जो मेरिटोरियस बेटे भी बेटी भी दोनों, दोनों के लिए जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको दिल्ली सरकार लैपटॉप देगी और उसके लिए भी हमने 10 करोड़ रुपये का फंड बनाया है। पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अध्यक्ष जी, हमने पिछली सरकार के जैसे कागजों में कमरे नहीं बनाने हैं। पिछली सरकार ने कहा जी हमने स्मार्ट क्लास बना दी, स्मार्ट क्लास बना दी। हमने जाकर खोजा तो हमें तो स्मार्ट क्लास मिली नहीं वहां पर कहां बनाई। अभी वो होते तो मैं पूछती पर है ही नहीं। परंतु हमने वर्ष 2025-26 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 7000 क्लासेज को स्मार्ट बोर्ड से लैस किया, स्मार्ट क्लासेज बनाई और वर्ष 2026-27 में 8777 क्लासेज में स्मार्ट बोर्ड लगाने का हमारा लक्ष्य है। टोटल हम चाहते हैं दिल्ली के हर स्कूल में, दिल्ली सरकार के हर स्कूल में, हर क्लास में स्मार्ट रूम होना चाहिए। 5 साल के हमारे कार्यकाल में इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। परंतु इस साल हमने 150 करोड़ रुपये का फंड मात्र स्मार्ट क्लासेज के लिए रखा है। दिल्ली में बच्चे शानदार परफॉर्मेंस करते हैं स्पोर्ट्स में पर उनके लिए हॉस्टल की कमी है। वो आएं तो रहें कहां। वो पूरा-पूरा दिन कई-कई घंटे लग जाते हैं ट्रैवल करके आने में। इस बार इस साल दिल्ली में स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल इत्यादि बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का फंड रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत में और वो भी दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट का महाकुंभ देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्सपोज़र विजिट ये सारे हमारे बच्चों के लिए भी जरूरी है और इस साल और ऐसा होता नहीं था दिल्ली सरकार के बच्चों को कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं लेकर जाया जाता था। कहीं नहीं कहा जाता था दूसरे राज्यों में जाकर के भई तुम भी कुछ एक्सपोज़र हासिल करो, पर अब दिल्ली सरकार ने हमने 18, साढ़े 18 करोड़ रूपये का बजट बच्चों के लिए इन एक्सपोजर्स विजिट्स के लिए रखा है इस बार के बजट में। मैं हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की भी बात करना चाहूंगी। हमने टेक्निकल एजुकेशन के हैड में 720 करोड़ रूपये का फंड रखा है। जहां पर हम शाहदरा, पूसा और जेल रोड

इन तीनों आईटीआईज के इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करेंगे। हम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के नए भवन का भी निर्माण हम इस साल करेंगे। उसके लिए अलग से 100 करोड़ रूपये का बजट हमने रखा है। दिल्ली सरकार स्किल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। एंप्लॉयमेंट बेस्ड ट्रेनिंग हम इसकी ओर आगे बढ़ते हुए आईटीआई जहांगीरपुरी, आईटीआई धीरपुर, आईटीआई शाहदरा, आईटीआई नरेला, आईटीआई नंदन नगरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम स्थापित करने जा रहे हैं। अब हमारा दिल्ली का युवा केवल जॉब सीकर नहीं बनेगा भाई, जॉब क्रिएटर के नाते हमारा दिल्ली का युवा डेवलप हो उसके लिए हम स्टार्टअप पॉलिसी ला रहे हैं, इनक्यूबेशन पॉलिसी ले आ रहे हैं और पूरा एक इनोवेटिव इको सिस्टम डेवलप करके हमारे बच्चों को हम ऐसी सेल्फ स्टैंडिंग देंगे कि वो अपने लिए खुद के लिए अपना व्यापार खड़ा करें और लोगों को जॉब देने वाले बने। हम दिल्ली में नरेला एरिया में नई एक इंटीग्रेटिड एजुकेशन सिटी बनाने की ओर अग्रसर है। इस वर्तमान साल में हमने साढ़े 1300 करोड़ से जमीन परचेज की है। इसी तरीके से अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार किया जायेगा। मुंडका में खेल विश्वविद्यालय का एक स्थाई परिसर बनाया जाएगा जो वर्ल्ड क्लास होगा वर्ल्ड क्लास। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने 10 करोड़ रूपये का फंड रखा है और दिल्ली में युवाओं का टैलेंट हंट की योजना लाते हुए 10 करोड़ रूपये का उसके लिए भी बजट रखा है। दिल्ली में एक भी सैनिक स्कूल नहीं था, इस साल हम दिल्ली में एक नया सैनिक स्कूल बनाएंगे उसके लिए भी हमने फंड रखा है। दिल्ली शहर की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट प्ले स्कूल्स हैं और उन प्ले स्कूल्स का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। हम दिल्ली में प्ले स्कूल पॉलिसी, प्राइवेट प्ले स्कूल पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि इन सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रेगुलराइज किया जाए। किसी एक फ्रेमवर्क में बांध करके नियम, नियमों के साथ उनको चलाया जाए इसके लिए हम पॉलिसी ले आएंगे। दिल्ली में ऐसे-ऐसे एरिया हैं जहां छोटे-छोटे घर हैं। वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं होती, लाइब्रेरीज नहीं होती। हम दिल्ली में कॉमन लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम जो कि 24 आवर्स खुली रहे ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो उनका नॉलेज रिसोर्स सेंटर भी हो और उनका एक्सेस भी वहां पर हो। हम जो स्पोर्ट्स और हैल्थ की ओर ध्यान देते हुए हमारे स्टेडियम्स में जब हमारे युवा खेलते हैं तो उनके लिए वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज का कोई सेंटर नहीं होता तो हम अपने स्टेडियम में रिहेब्लिटेशन सेंटर स्थापित करेंगे। हम प्राइवेट एकेडमीज जो होती हैं उनके साथ में इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि हमारे स्कूल के बच्चे उन प्राइवेट एकेडमी से लाभ उठा पायें और प्राइवेट एकेडमीज को हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो ताकि पूरी दिल्ली में हर बच्चे को खेल की बेस्ट ट्रेनिंग और हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाए तो शिक्षा हमारे लिए पहले भी प्रायोरिटी था और भविष्य में भी हमेशा प्रायोरिटी रहेगा और जहां-जहां भी जिस विधानसभा में भी अभी स्कूल नहीं है विशेष रूप से हमारा ध्यान रहेगा कि उन विधानसभाओं में पहले स्कूल बनाया जाए और केंद्र सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली को इस साल कम से कम 10 केंद्रीय विद्यालय दें, केंद्रीय विद्यालय, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बात करना चाहूंगी अब सोशल एंपावरमेंट की समावेशी विकास और सबका सशक्तिकरण, लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और पथ भी अंत्योदय, दीनदयाल जी का यह विचार हमेशा से हमारा

मार्गदर्शक रहा है और इस बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए हमने 2 हजार 3 सौ 92वे करोड़ रूपये का बजट रखा है, 2 हजार 3 सौ 92वे करोड़ रूपये का और एससी, एसटी और ओबीसी समाज कल्याण हेतु 227 करोड़ रूपये का अलग से प्रावधान किया। अनुसूचित जाति बस्तियों के सुधार के लिए 80 करोड़ रूपये का फंड दिया जाएगा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक ठोस कदम होगा। हमने मेंटली चैलेंजड व्यक्तियों के लिए मामरपुर में, नरेला में, उस्मानपुर में आवास बनाने की जो योजना है उसके लिए 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। और इसी तरीके से जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उन सबको रेनोवेट करना, विशेष रूप से हमारे वो बच्चे जिनके पास आंखें नहीं है वर्षों से टूटी हुई बिल्डिंग में अपना गुजारा कर रहे थे इस वर्ष उन बच्चों के लिए भी नई बिल्डिंग बना करके दी जाएगी। अध्यक्ष जी पिछली सरकार के दौरान जब हम सब चुनाव में थे और वर्षों से सुन रहे थे तो हमारे दिल्ली के बुजुर्ग बड़े परेशान थे। आपके यहां भी बहुत सारी बुजुर्ग संस्थाएं हैं। सीनियर सिटीजंस की एसोसिएशन है और वह हमेशा बेचारे परेशान होकर के हमारे पास आ रहे थे कि भाई वो पिछली सरकार कोई पैसा देती थी और चार-पांच साल से मिल नहीं रहा तो हमें लगा कैजुअली कि नहीं दिया होगा पैसा उनकी मर्जी थी हमने उनको कह दिया वायदा कर दिया कि दे देंगे पर जब सरकार में बैठकर के देखा तो ना तो उस नाम की कोई योजना थी, ना उस मद में कोई पैसा था और वो कहां से पैसा निकाल के दिया ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जांच का तो जैसे ही यह पता चला 4 साल पहले तो वो योजना बंद हो गई। कभी सरकार ने यह नहीं बताया कि हम गलत तरीके से वह पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और यह योजना बंद हो चुकी है परंतु लोगों की आस में था कि शायद हमें पैसा मिलेगा। परंतु उस आस को पूरा करने का काम उस आस को पूरा करने का प्रयास हमारी वर्तमान की सरकार करेगी, इसके लिए हम नई योजना बना रहे हैं। नई योजना जिसका नाम होगा वयो आनंद, उन वृद्ध लोगों को आनंद के लिए रिक्रिएशन के लिए सरकार पहले तो मुट्ठी भर संस्थाओं को पैसा मिलता था पर हम इस बार ज्यादातर संस्थाओं को जो भी इस कैटेगरी में आना चाहेगी हमारे नियमों के तहत उन सबको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए पैसा देंगे और इस मद में हमने 25 करोड़ रूपये रखा है इस योजना के माध्यम से काम करेंगे। हम दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करें, दिल्ली के विकास की बात करें और झुग्गी-बस्तियों की बात नहीं करेंगे तो यह दिल्ली के विकास के साथ न्याय नहीं होगा। हमने ड्यूसिब के माध्यम से जे.जे. कॉलोनियों, बस्ती विकास के लिए, सामुदायिक ढांचों के लिए टॉयलेट ब्लॉक्स के लिए, नाली खरंजा सड़क के लिए और अटल कैंटीन जो एक शानदार प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने पिछले साल शुरू किया इन सबके लिए मैंने तो कई आपियों को भी वहां भोजन करते हुए देखा है। जब उनको घर में नहीं होता कहते वहां बढ़िया खाना है वहां खाने चलेंगे तो यह इस मद में हमने 634 करोड़ रूपये का फंड हमने रखा है ताकि कोई पीछे ना छूटे, कोई वंचित ना रहे और दिल्ली का समग्र विकास हो और जो बात थी कि झुग्गियों को मकान देने की बात उस दिशा में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साबदा घेवरा में हमने लगभग 2400 फ्लैटों की मरम्मत का काम शुरू कर चुके हैं और द्वारका, सुल्तानपुरी और भलसवा में भी इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को रिपेयर करने का काम हम शुरू करेंगे और इन सबको हर झुग्गी को अपना पक्का घर मिले इस पर हम काम कर रहे हैं अपनी बात पर पूरी तरीके से अडिग हैं। अब मैं एक विषय जो मेरे दिल के बड़ा नजदीक है उस पर बात करना चाहती

हूं और मेरा विभाग भी है महिला एवं बाल विकास विभाग इस हेड में हमने 7406 करोड़ रूपये का बजट रखा है अध्यक्ष जी महिला एवं बाल विकास विभाग में और मैं सबसे पहले जो कहना चाहती हूं महिला समृद्धि योजना दिल्ली की बहनों को हमने 2500 रूपये देने का वादा किया था प्रतिमाह, और इस वादे पे हम अडिग हैं। हमने इसके लिए 5110 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है इस साल और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली की बहनों को इस योजना का लाभ हम दें। पर क्योंकि यह योजना रेगुलर चलने वाली हर महीने की योजना है और बहनों को वो बहनें जो सच में इस लाभ की अधिकारी हैं, पात्र हैं उनको यह लाभ मिले। उसके लिए हमने एक विशेष जांच कमेटी बनाई थी जो इस पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें लाकर के दे रही है। जिसमें किस तरीके के वर्ग को इसका सीधा लाभ चाहिए उस पर काम हो रहा है। बहुत जल्द हम दिल्ली सरकार का वो पोर्टल खोलेंगे जिस पे बहनें इस योजना के तहत अप्लाई कर सकेंगी। जो कोई चीज नहीं होती तो यह सामने वाले लोग उचक-उचक के बोलते हैं सब कुछ हो गया। एक साल की उपलब्धियों पे जब हमने बात रखी अब उन्हें लगा सब हो गया तो क्या बोले? तो एक ही चीज थी। 2500-2500 ये नहीं बोले कि सिलेंडर दे दिया तुमने जब होली पे हमने 128 करोड़ की सीधा डीबीटी करी। किसी को चक्कर नहीं लगवाया कि आओ सिलेंडर लेके जाओ। और खाली सिलेंडर वालों को नहीं अध्यक्ष जी। जिसके यहां पाइपलाइन थी उसको भी दिया। साढ़े 17 लाख परिवारों के लिए हमने होली के त्यौहार पे सिलेंडर की वैल्यू के 853 रूपये उनके खातों में भिजवा दिए थे। और इस साल भी हमने 260 करोड़ रूपये का फंड रखा है। होली और दिवाली पे एक-एक सिलेंडर दिल्ली की बहनों को दिल्ली के परिवारों को देने के लिए। अध्यक्ष जी, दिल्ली में महिलाओं को फ्री ट्रैवल, फ्री ट्रैवल की बात आती है हमने उसको जारी रखा। हमने कहा बिल्कुल देंगे और इस बार के इस बजट में भी हमने 450 करोड़ रूपये केवल दिल्ली की परिवहन बसों में बहनों को फ्री ट्रैवल देने के लिए हमने 450 करोड़ रखे हैं भाई। पूरी तरीके से देंगे। प्रतिबद्ध है। पर भ्रष्टाचार के लिए 1 रूपया भी नहीं रखा। हमने पिंक कार्ड बनवाया इसीलिए कि जितनी बहनें ट्रैवल करेंगी उतनों को हम उतने हेड में हम पैसा देंगे। 1000 बहनें ट्रैवल करेंगी। 1000 बहनों का नाम का पैसा मिल जाएगा। पर इसमें करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए हमने यह पिंक सहेली कार्ड बनाए हैं। और इसमें अब केवल महिलाएं नहीं अध्यक्ष जी हमने दिल्ली के ट्रांसजेंडर वर्ग को भी दिल्ली की डीटीसी बसों में मुफ्त ट्रैवल दिया है। यह भी एक बहुत बड़ी सौगात है ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए। अध्यक्ष जी, इसी श्रृंखला में हमने एक बहुत ही प्यारी योजना दिल्ली लखपति बिटिया योजना दिल्ली की बेटियों को पढ़ने का पूरा मौका मिले एक योजना पहले होती थी लाडली, लाडली बहुत पुरानी योजना थी पर कहीं से कहीं तक भी उस योजना की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कोई जुड़ाव नहीं था किसी ने फॉर्म भरा सरकार ने उसके खाते में पैसा डाला कोई वापस लेने आ रहा है, नहीं आ रहा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कौन इसका लाभ उठा रहा था, कौन पैसा खा रहा था, कुछ नहीं मालूम। पर हमने इस योजना को बंद करके दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करी। जिसमें अब हम दिल्ली में पैदा होने वाली हर उस बेटी को जो हमारे उस क्राइटेरिया में आती है। जन्म से लेके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक उसके खाते में लगातार पैसे डालेंगे और जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तो लगभग 1,20,000 हमारी उस बेटी को मिलेंगे। और इस हेड में अरे दिल्ली की बेटियों की बात है ताली जोरदार होनी चाहिए।

और इस हेड में हमने 128 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है और इस योजना को हमने पूरा प्रोसेस डिजिटल प्रोसेस किया है। आसान रजिस्ट्रेशन किया है। क्योंकि अब दिल्ली की बेटी पढ़ेगी भी और बढ़ेगी भी। बात जब महिलाओं के लिए योजनाओं की हो रही है। आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हो रही है। तो एक हमेशा से जरूरत महसूस की जाती है कि वो बहनें जिनके हाथ में हुनर है उनको कोई स्पेसिफिक बाजार नहीं मिलता। कोई हाट नहीं मिलता। दिल्ली में हम अब से अपनी बहनों के टैलेंट के लिए उनके हुनर के लिए उनके हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के लिए उनके व्यापार के लिए महिला हाट खोलने जा रहे हैं। और इस मद में हमने 10 करोड़ रूपये का फंड रखा है। दिल्ली में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चाहेंगे कि हर बहन अपने पैरों पर खड़ी हो। अपने हाथ में ऐसा हुनर रखे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इस काम को बढ़ाएंगे। उन हाटों को बनाएंगे और एक छोटी सी रानी बनकर के हमारी यह बहनें अपने जीवन को चलाएंगी। अपने परिवार को चलाएंगी। इसलिए हमने उन हाटों का नाम भी रानीहाट सोचा है। रानीहाट बनेंगे दिल्ली में बहनों के लिए उनके हुनर के लिए। दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्षों से चल रही है। बड़े पुराने-पुराने विधायक लोग बैठे हैं कई कई बार के। वर्षों से आंगनवाड़ी किराए की बिल्डिंग्स में बुरी हालत में पानी शौचालय कोई बिना व्यवस्था के चल रही है। पर हमने हर आंगनवाड़ी को मॉडल आंगनवाड़ी के लिए डेवलप करने के लिए लगातार काम शुरू किया। हमने पालना सेंटर खोले जो हमारी मजदूर और श्रमिक बहनों के लिए जहां उनके बच्चों की देखभाल हो सके और बहनें अपना काम कर सके। उस हेड में भी पालना के हेड में भी हमने फंड रखा है और ये जो आंगनवाड़ी है इस हेड में भी हमने 33 करोड़ रूपये का फंड रखा है जो दिल्ली में बच्चों की विकास के लिए उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ही जरूरी काम है। दिल्ली में बहनों की सुरक्षा की बात अक्सर आती है। बहनों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा। मैं यह बताना चाहती हूं कि लगातार अपने इस एक साल के कार्यकाल में दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बहुत ही कंसर्न भी हैं और उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण काम मैं इस बजट के माध्यम से बताना चाहती हूं। एक, दिल्ली में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं जितने भी अब वहां पर जो पहले वह लाइटें होती थी पीली वाली लाइटें उन लाइटों को हटा करके बहुत ही शानदार नई लाइटें जो कि पूरी तरीके से सेंसर्ड होंगी कहीं पे कोई भी लाइट बंद होगी तुरंत पता चल जाएगा और ये स्ट्रीट लाइट ऊर्जा कुशल होंगी स्मार्ट एलईडी होंगी और जिसकी विजिबिलिटी बहुत शानदार होगी ₹50 करोड़ का फंड हमने सड़कों की सुरक्षा ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए उसके लिए रखी है। दिल्ली में कैमरे तो बहुत लगाए पिछली सरकार ने पर वो कैमरे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे ये किसी को नहीं पता क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो पता चलता है वही वाला कैमरा बंद था। वही कैमरा नहीं चलता था। तो फिर पता चला कि एएमसी आधे से ज्यादा कैमरों की एएमसी नहीं है। खराब पड़े हैं। ठीक नहीं है। यह भी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक साबित हो सकता है। हमने अपने इस फंड में सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 225 करोड़ रूपये का फंड रखा है। जिसमें 50 हजार नए कैमरे और इन सारे कैमरों की एएमसी के लिए इसमें फंड रखा है, ताकि कोई भी कैमरा खराब ना हो और तुरंत ठीक किया जाए। हमने अध्यक्ष जी, 16 करोड़ रूपये वन स्टॉप सेंटर जो कि महिलाओं को संकट की घड़ी में मदद देने वाले

हैं। 11 नए सेंटर हम खोलने वाले हैं उसके लिए 16 करोड़ रूपये रखा है। अब एक बड़ी योजना ये भी मैं बताना चाहती हूं बहनों के लिए है, परेशान ना हो आप, पर बहनों को मजबूत करोगे तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो पूरा समाज मजबूत होगा। जब मैं बजट पे डिस्कशन कर रही थी तो मैंने दिल्ली की उन बहनों को बुलाया जो ऑटो चलाती हैं, जो टैक्सी चलाती हैं, जो बाइक चलाती हैं, टू व्हीलर चलाती हैं। मैंने पूछा भई क्या मदद चाहिए तुम्हें बताओ? तो उनकी व्यथा सुनके मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा जी हम दिन भर मेहनत करते हैं। दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं। 14 घंटे भी काम कर लेते हैं। पर जितना पैसा एक दिन में कमाते हैं उसमें से आधा तो किराए पे निकल जाता है। क्योंकि परमिट हमारे नाम का नहीं है। ये परमिट जिसके नाम का होता है वो गाड़ी हमें किराए पे देता है। फिर हम चलाते हैं और उसमें से कोई छुट्टी नहीं। कोई मतलब नहीं। रोजाना पैसा कट जाता है। कुछ बचता ही नहीं है। मैंने कहा तो क्या चाहिए? बताओ। कह रहे हमारे नाम का परमिट मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे सुनो तो, सुनो तो, दिल्ली में हम 1000 बहनों को, 1000 बहनों को ई ऑटो का परमिट देने जा रहे हैं। वो भी बिना किसी कॉस्ट के। नए परमिट 1000 ई ऑटो के लिए और 100 ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यानी 1100 ई ऑटो परमिट दिल्ली की बहनों को देंगे, उनके नाम का जो वो खुद चलाएंगी। खुद अपने पैरों पर खड़ी हो के अपनी मेहनत से अपना परिवार, अपना घर-वार ये चलाएंगी। ऐसी 1100 ई ऑटो के नए परमिट दिल्ली सरकार देगी। उपहार देगी दिल्ली की बहनों को और बताना चाहूंगी एक और हमारे बाल सुधार ग्रह होते हैं। बाल सुधार ग्रह में वो बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। हमने इस बार एक बड़े बजट के साथ में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स अलीपुर में बनाने का प्लान किया है। जहां ये बच्चे जो अलग-अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में होते हैं, वहां लाए जाएंगे। पर गुनाह के साथ आएंगे जरूर पर अपने साथ जब वापसी जाएंगे तो वो ले के जाएंगे हाथ का हुनर। हम इन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे ताकि दिल्ली में कोई भी बच्चा कभी भी गुनाह के बोझ के नीचे ना दबे। उसका एक भविष्य उसका इंतजार करें। उसके हाथ का हुनर उसका इंतजार करें और वो अपना बेहतर जीवन कर सके और ऐसे ही हमारे होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर। इन चाइल्ड केयर सेंटर में वो लोग रहते हैं जिनके अपने मां-बाप नहीं होते हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं सरकार की गार्डियनशिप में ही रहते हैं और हमारे सरकार के ही बच्चों के नाते हम उन्हें पालते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाए क्या इनका भविष्य होगा? क्या इनका रोजगार होगा? इसकी चिंता भी शत प्रतिशत हमें ही करनी होगी। तो हमने तय किया है कि इस हेड में हम फंड रख कर के एक आफ्टर केयर फंड बनाएंगे ताकि इन बच्चों को उनका व्यापार, रोजगार और अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति मिले ताकि ये दिल्ली सरकार के वो बच्चे आगे बढ़ पाए, अपना सफल जीवन कर पाए। अध्यक्ष जी इसी श्रृंखला में इसी विभाग में दिल्ली की हमारी बेटियों के लिए जो स्कूलों में पढ़ती हैं। हमने हर साल ढाई करोड़ सेनेरी नैपकिंस बांटने का भी विचार किया है। दिए अभी भी जाते हैं पर उसकी जो संख्या है वो पूरी नहीं है, तो दिल्ली की बेटियों को न्यू सेनेरी पैड वेंडिंग मशीनें हम लगाएंगे स्कूलों के अंदर। उनको ढाई करोड़ सेनेरी नैपकिन हर साल दिए जाएंगे ताकि इन बच्चों की स्वास्थ्य और इनके हाइजीन का ध्यान रखा जा सके। एक बड़ी संख्या दिल्ली में गिग वर्कर्स की है। गिग वर्कर्स बहुत सारी समस्याओं के साथ रोज जूझते हैं। मैंने उनको बुलाया, उनको बिठाया, उनसे बात

की तो उनकी समस्याओं को देखते हुए दो निर्णय फिलहाल हमने किए हैं। एक इन सभी गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम। ये कहते हैं हम घंटों चलते हैं अपने टू व्हीलर्स पे। हमारे पास पर कोई ऐसा स्थान नहीं होता कि जहां बैठे दो घड़ी आराम से खाना खा लें या अपना मोबाइल चार्ज कर लें। कई बार तो इतनी थकावट के कारण हमारे एक्सीडेंट होते हैं। हम दिल्ली में अपने गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के साथ जोड़ते हुए रेस्ट रूम बनाएंगे। जहां उनका भोजन, उनका रेस्ट, उनकी मोबाइल चार्जिंग ये सारे काम हो पाए और साथ ही गिग वेलफेयर बोर्ड का गठन भी तुरंत करेंगे ताकि बाकी समस्याओं का समाधान भी बने। बोर्ड और भी बनने हैं पर थोड़ा उसमें काम करने में हमें समय लगा। पर फिर भी मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। दिल्ली में हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर का वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे। दिल्ली में हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे और दिल्ली में हम गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे ताकि सारे वर्ग को हम अपनी सुविधाएं दे सके उनको सेवा दे सके । अध्यक्ष जी ये समाज जो है, इस समाज में जब हम बात करते हैं बुजुर्गों की, महिलाओं की, पुरुषों की, बेटों की, बेटियों की पर एक वर्ग है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए वो है पशु, पशु और पक्षी ये भी समाज का अभिन्न अंग है। हमें इन पशु पक्षियों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने करुणा भाव से दिल्ली में वेटनरी हॉस्पिटल्स के रेनोवेट करने के लिए उनको मॉडर्नाइज करने के लिए वहां पर चिकित्सा, पशुओं की देखभाल, आधुनिक उपकरण सर्जरी, टीकाकरण इन सब की व्यवस्था करने के लिए 62 करोड़ रूपए का फंड हमने रखा है। सरकार इंसानों की नहीं जीवो की भी पूरी चिंता करती है। दिल्ली में बहुत से डॉग लवर्स हैं। सभी हैं, हम सब भी हैं। और उन कुत्तों को फीड करने के लिए उनको प्यार बांटने के लिए हम दिल्ली में डॉग शेल्टर बनाएंगे। जहां पे लोग जाकर के सेवाएं दे पाएंगे। उनको भोजन करवा पाएंगे और कोई बीमार डॉग हुआ तो उसको वहां पे वो छोड़ के भी आ सकते हैं। तो दिल्ली में हम गायों के लिए, हम डॉग्स के लिए, हम पक्षियों के लिए इन सबके लिए भी करुणा भाव से काम करते हुए सुविधाएं देंगे। दिल्ली में बहुत सारी गौशालाएं दिल्ली सरकार के सहयोग से चल रही थीं पर वर्षों से उनका फंड उन्हें दिया ही नहीं गया था। हमारी सरकार आने के बाद ना केवल हमने उनकी पुरानी देय राशि दी है बल्कि जो लीज वर्षों से उनकी रिन्यू नहीं हुई थी वो सभी गौशालाओं की लीज भी हमने रिन्यू की है और इस साल 14 करोड़ रूपए इस हेड में नए रखे हैं और 10 नई गौशालाएं समाज के सहयोग से बनाने का हमारा काम है। हमारी योजना है।

अध्यक्ष जी सारी बातें हो गईं। डॉक्टर पंकज सिंह हमारे मंत्री जी मुझे देख रहे हैं। कह रहे मेरा विभाग रह गया। आया नहीं अभी। आ गया, आ गया। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक ग्रीन सस्टेनेबल और कंजेशन फ्री परिवहन व्यवस्था दिल्ली में होनी चाहिए। हम सब जानते हैं। हम चाहते हैं और इसके लिए हमने अपने बजट 2026-27 में 8374 करोड़ रूपए का फंड रखा है और मैं बधाई देना चाहती हूं अपने परिवहन विभाग को शानदार काम कर रहे हैं। हर महीने 4-5 सौ बसें बढ़ाकर के देते हैं। आज की डेट में हमारी जो ईवी बसों की फ्लीट जो है वो 4300 बसें। देश में सबसे ज्यादा है अध्यक्ष जी 4300 बसें हो गई हैं। इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है मार्च 2027 तक हम दिल्ली में 7500 बसें हो जाएंगी और उसमें से 5800 बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी। एमिशन फ्री दिल्ली

के पर्यावरण को सूट करने वाली। दिल्ली में प्रदूषण की मार को खत्म करने वाली, कम करने वाली और 2029 तक हमारी कोशिश है कि 100% फ्लीट जो दिल्ली की है परिवहन बसों की वो पूरी तरीके से ईवी हो। 12,000 बसें अब दिल्ली को ईवी बसें देने वाले हैं। मेट्रो एक बहुत बड़ा साधन है परिवहन का। पिछली सरकारों ने जितनी मर्जी बातें की हों। कभी मेट्रो को पैसे नहीं देते थे। मेट्रो की झंडी फैलाने आ जाते थे पर पैसे देने के नाम पे गायब। कोई मतलब नहीं था उनका। पर हमने अपने इस वर्तमान फाइनेंसियल ईयर में पिछली सरकार के हेड में भी पैसे दिए। लगभग 8000 करोड़ की देनदारी थी। हमने उसमें से लगभग पिछली सरकार के हिस्से के 2700 करोड़ दिए। अपने हिस्से के जो फेज फोर की मेट्रो का रूट है उसके लिए हमने 3000 दिए और वर्तमान बजट 2026-27 के लिए 2885 करोड़ रूपए हमने प्रस्तावित किया है। नमो भारत कॉरिडोर ये भी एक शानदार दिल्ली के लिए वो सौगात जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है जिसमें दिल्ली पानीपत, दिल्ली सोनीपत, दिल्ली एसएनबी ये सारे रूट पे जबरदस्त डीकंजेशन होगा जबरदस्त, लाखों लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं और उसके लिए हमने अपने इस बजट में 5 सौ 68 करोड़ रूपये का फंड रखा है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी पिछली सरकार ने भी बनाई थी एक छोटी-मोटी सी। बनाई थी, पैसा नहीं दिया, पैसा हमने आने के बाद दिया। उनको भी पता था रेखा गुप्ता जी आएंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी, हमारे नाम का पैसा वही देंगी। तो उन्होंने कभी पैसा नहीं दिया था ईवी में, हमने अभी पिछले हफ्ते 24 करोड़ रूपये 2023 से पेंडिंग ईवी व्हीकल को जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो अब आके दिया है। परंतु अपनी सरकार हम ईवी पॉलिसी जो लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने पहले से ही 200 करोड़ रूपये का फंड रख दिया है और शानदार योजना के साथ जिसमें परचेस, स्क्रैप प्रोत्साहन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो एमिशन मोबिलिटी ये सारी चीजों के लिए दिल्ली को गति देने के लिए, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने के लिए, दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में अपना एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए देश की सबसे बड़ी ईवी पॉलिसी दिल्ली लेकर के आ रही है। सबसे बड़ी पॉलिसी अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं, दिल्ली लेकर के आएगी। मैंने पहले ही बताया कि हमारा 21% सब लोग ईवी ले लो भाई। मैंने पहले ही बताया कि हमारे बजट का लगभग 21% हम ग्रीन बजट के नाते से खर्च करेंगे। दिल्ली में कभी टेस्टिंग सुविधा 6.5 लाख कमर्शियल व्हीकल है पर उनकी टेस्टिंग वो जाकर के दिल्ली से बाहर कराते थे। कराते थे कि नहीं कराते थे पता नहीं, हमने पिछले 1 साल में उस पर बहुत बड़ा काम किया। तीन नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस हमने पिछले साल काम शुरू करवाया और इस साल पांच नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बवाना, गाजीपुर, सावदा घेरा, जीटी करनाल रोड, दिचाऊं कलां इन विभिन्न डीटीसी डिपोज़ में पांच नए एटीएस हम बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमने 50 करोड़ रूपये रखा है। ₹50 करोड़ का फंड और दिल्ली में बस डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 320 करोड़ रूपये का अलग से फंड रखा है। हम दिल्ली को शानदार कनेक्टिविटी देना चाहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति घर से निकले तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो अपना व्हीकल ना उठाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाए इसके लिए सारे काम दिल्ली सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। ई बाइक, ई ऑटो, ई टैक्सी, भारत टैक्सी ये सारी चीजें जो जीरो एमिशन के साथ में हमेशा दिल्ली के लिए

कार्यरत रहे इसके लिए दिल्ली सरकार कार्य कर रही है। और दिल्ली का डेवलपमेंट रैंडमली नहीं होना चाहिए। दिल्ली का डेवलपमेंट बड़े प्लैंड तरीके से दिल्ली को जाम मुक्त करना है, कंजेशन फ्री करना है, कैसे होगा? कहां फ्लाई ओवर बनेगा? कहां एलिवेटेड रोड बनेगी? कहां पूरा जो योजना हमारे मंत्री जी ने सोची कि एक पैरेलल रिंग रोड बनानी है। तो ये सब चीजें केवल सोचने से नहीं होगी। पिछली सरकार में मंत्री जाता था चार मंजिल बन गई, बिल्डिंग कहता था दो और बना दो, वो कहते सर नक्शा पास नहीं है वो कह रहे क्या हो गया? कि सर इसका सेफ्टी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, कह रहे क्या हो गया? कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्टडी नहीं, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं, पर हम लोगों ने इस साल 10 करोड़ रूपये रखा है फिजिबल स्टडीज के लिए, साइंटिफिक स्टडीज के लिए कि दिल्ली को कैसे जाम मुक्त करना है, कंजेशन फ्री करना है, कहां फ्लाई ओवर, कहां रोड, कहां एलिवेटेड रोड, पूरी दिल्ली की मैपिंग करके इन सारे कामों को हम करेंगे। यह हमारा उस लॉन्ग टर्म विज़न के साथ करने वाले प्रयास हैं, अध्यक्ष जी।

एक बात जरूर जो मैं कहूंगी जो हमने सीखा केंद्र से, हमारे नेताओं से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमेशा गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने की, ईमानदारी की, ट्रांसपेरेंसी की, जवाबदेही की, सेवा की बात उन्होंने कही और उन्हीं के उसी मूल मंत्र के साथ दिल्ली लगातार आगे बढ़ रही है। हमने हमारी सरकार ने दिल्ली में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस करने के लिए डीसेंट्रलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता है और इस पूरे विभाग के लिए इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने 4304 करोड़ रूपये के बजट का आवंटन रखा है, 4304 करोड़ का। दिल्ली में हमने 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए और एमसीडी और दिल्ली के जिलों को कोटर्मिनेंस किया। अब उन 13 जिलों के मिनी सचिवालय बनाने हैं। जो जन संवाद के सीधा केंद्र होंगे। एक जो दक्षिणी पश्चिम जिले का मिनी सचिवालय है उसकी योजना पूरी कर ली गई है। उसके हेड में इस साल हमने 213 करोड़ रूपये का फंड रखा है और 2026-27 में बाकी के 12 मिनी सचिवालय बनाने के लिए हमने 100 करोड़ रूपये का और फंड रखा है। 13 के 13 नए मिनी सचिवालय बनेंगे। जहां लोग जाएंगे, अपने काम करवाएंगे, एक ही छत के अंतर्गत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसिसेस वहां पे लोगों को मिलेंगे। अध्यक्ष जी मोदी जी कहते हैं अच्छा शासन जो है जन आंदोलन बनना चाहिए और इसीलिए दिल्ली में जितने लैंड रिकॉर्ड हैं उन सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के लिए उनको एक यूनिक आईडी देने के लिए दिल्ली सरकार काम करेगी ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और दिल्ली आगे बढ़े। हम दिल्ली में जैसे केंद्र में नीति आयोग काम करता है उसी तर्ज पर दिल्ली में दित्ती आयोग Delhi Institutional Think Tank for Innovation ये दित्ती आयोग बनाएंगे जो दिल्ली के लिए पूरा इनोवेटिव प्लानिंग करेगा काम करेगा दिल्ली को नए विज़न के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमारे आने से पहले डीएम के पास कोई पावर नहीं होती थी पैसा नहीं होता था कि वह अपनी मर्जी से कहीं 10 रूपये भी खर्च ले। एरिया में कोई काम आए तो किसी काम में वो कुछ भी खर्चा बोल दे। हमने आने के बाद डीएम्स की पावर बढ़ाई और इस साल हम डीएम को जिला स्तर पर विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 59 करोड़ रूपये का बजट इस साल हम प्रस्तावित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी हमने सीएम जन सुनवाई पोर्टल

तैयार किया है ताकि जनता तुरंत हम फिजिकल भी मिलते हैं, हमारे पोर्टल पे भी समस्या केवल घूमती ना रहे, समस्या को समाधान मिलना चाहिए, हमने दिल्ली की कितनी एसेट है उसका Delhi Asset Management and Information System develop किया। अरे सरकार को पता तो हो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहां है पता ही नहीं है, लोग कब्जा कर रहे हैं जमीनों पे, लोगों की मिलीभगत है, नेताओं की मिलीभगत थी, अभी वो बैठे नहीं है सामने, इनके सामने बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग तो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर करके बैठे हैं। किसी ने घर बना लिया, किसी ने दफ्तर बना लिया, दिल्ली सरकार की एक भी संपत्ति किसी से कब्जा नहीं होने देंगे। हमने पूरा Asset Management Information System हम शुरू कर रहे हैं। अब इतने सारे प्रोजेक्ट हैं उनकी प्रगति को देखने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल बनाया गया है। 5 करोड़ का फंड हमने उसमें भी रखा है। एक-एक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट पता चलता है। किस स्तर पे है? क्या काम है? क्योंकि जितनी बातें कही है वह समयबद्ध तरीके से पूरी होनी भी बहुत जरूरी हैं। हमने Integrated Financial Management System develop किया है ताकि पूरा वित्तीय संचालन जो है सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से हो और हमारी सरकार ने पूरी ई फाइलिंग के माध्यम से दिल्ली में पारदर्शी और जवाबदेह शासन क्रिएट किया है। एक अध्यक्ष जी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूं। दिल्ली में जो सब रजिस्ट्रार स्तर पर जो पंजीकरण होता है, प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री होती है या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। लोग बहुत परेशान रहते हैं। वर्षों का ये सिस्टम बना हुआ है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उस सिस्टम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। जहां मानव जो दिल्ली का नागरिक है वो जाए तो बहुत सुविधाजनक तरीके से बिना किसी करप्शन के, बिना किसी को पैसा दिए हुए उसका काम होना चाहिए और इसके लिए हम केंद्र का जो पासपोर्ट ऑफिस वाली तर्ज पे दिल्ली के सारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कार्यवाही करेंगे जो कि पूरी तरीके से मॉडर्न होगी, पेपरलेस होगी और फेसलेस होगी। ये सारा रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। दिल्ली में नई व्यवस्था खड़ी करी जाएगी जो पूरी तरीके से ईमानदारी, जवाबदेही और बहुत ही मॉडर्न तकनीक के साथ लाई जाएगी।

अध्यक्ष जी, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है disaster management अभी पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश पर संकट के बादल थे, हमें भी दिल्ली को भी डर था कि भई कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसी हमारे राज्य पर विपत्ति ना आए तो हमने पूछा अधिकारियों से सीएस साहब बैठे हैं मैंने कहा कि भाई कोई हमारा भी disaster management का system होगा, कोई integrated वो होगा कॉम्प्लेक्स। हैरानी की बात है सालों से कभी किसी सरकार ने इस चीज की चिंता नहीं की कि दिल्ली में कोई emergency operation centre हो, कोई disaster management का कोई बिल्डिंग हो जहां सारी की सारी दिल्ली integrated रूप में दिखाई दे सके, जहां फैसले हो सके, कुछ नहीं है| पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा DDMA के माध्यम से State of Art, emergency operation centre बनाया जाएगा और उसके लिए हमने ₹10 करोड़ का प्रावधान इस साल रखा है, जगह भी तय कर दी है भैया, 5-श्यामनाथ मार्ग जगह भी तय कर दी है, वहीं बनाएंगे दिल्ली disaster दिल्ली का integrated जो Delhi level

पर, state level पर बनेगा, यह वहीं बनेगा। मैं साथ ही में एक सुलभ, कुशल और उत्कृष्ट न्यायपालिका प्रदान करने की दिशा में भी दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है।

न्यायालयों की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और उसको महत्वपूर्ण उसमें काम करना, यह हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हमने शास्त्री पार्क, कड़कड़डुमा, रोहिणी, राउस एवेन्यू, इनमें अतिरिक्त न्यायालय कक्ष और परिसर स्थापित करना, रोहिणी में एक नई family court की स्थापना करना और इन सब के लिए हमने ₹230 करोड़ का fund हमने इस साल रखा है।

अध्यक्ष जी, FIR होती है, आगे की कार्यवाही रुक जाती है। क्यों रुक जाती है कि forensic की रिपोर्टें नहीं आ पाती। हमने इसको priority पर लिया ताकि सारी complaints का, सारी FIR का, सारे cases का निपटान जल्द हो। हमने पिछले साल छह forensic वैनों को शुरू करी और इस साल forensic science laboratory खोलने के लिए हमने fund का provision किया है ताकि दिल्ली में जितने भी cases हैं उसकी तुरंत forensic जो रिपोर्ट आनी चाहिए वह रिपोर्ट उनको मिले और कोई भी एक भी रिपोर्ट पेंडिंग ना रहे, इसके लिए इस पूरे system को डेवलप करने के लिए काम चल रहा है। अध्यक्ष जी, एक हाई सिक्योरिटी जेल नरेला में हमने केंद्र सरकार की मदद से बनाने के काम की शुरुआत कर चुके हैं जिसे इस साल में आगे बढ़ाया जाएगा।

अब एक विभाग आदरणीय सिरसा जी का, सिरसा जी कह रहे हैं भाई इंडस्ट्री का नंबर। बिना इंडस्ट्री के क्या है? इंडस्ट्री किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि production driven और growth oriented economy तभी हो सकती है जब वहां industries बेहतर हो और सालों से हमारी दिल्ली के industrial sector में कुछ किया ही नहीं गया। एक service state मान करके ही सारी चीजें चल रही थी। जो industrial area बनाए गए, ऐसे के ऐसे पड़े हैं, कोई development का काम नहीं, कोई सड़क नहीं, नाली नहीं, कुछ भी नहीं था परंतु हमारी सरकार ने आने के बाद इन सब पर काम करना शुरू किया है। Small और medium enterprises को competitiveness और उनकी productivity बढ़ाने के लिए common facility centre बनाए जाएं, उसके लिए सरकार ने 48 करोड़ रूपये का fund industrial sector के लिए रखा है। Industrial area को बेहतर infrastructure, modern facilities और productivity के लिए जो जो भी सुविधाएं चाहिए सड़क, drainage, आपकी facilities, उन सबके लिए इस बार industrial sector में दिल्ली सरकार बेहतर काम करेगी और warehousing sector के लिए भी हम एक नई warehouse policy लेके आएंगे, उसका provision हमने ₹10 करोड़ इस साल रखा है नई warehouse policy के लिए। Efficient और modern logistic hub विकसित करने के लिए महोदय MSMEs दिल्ली की अर्थव्यवस्था की backbone है, दिल्ली को मजबूती देने के लिए हमने MSMEs के skill development के लिए, digital integration के लिए काम शुरू किया है और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में पहली बार ramp raising & accelerating MSME performance इस स्कीम को हमने दिल्ली में लागू किया है ताकि हमारे जो MSME सेक्टर के लोग हैं उनको स्किलिंग

की जाए, उनको अच्छी बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और 32,000 MSMEs को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत 15,000 बिजनेसिज को जैम पोर्टल से जोड़ा जाएगा और ONDC जैसे डिजिटल प्लेटफार्म से भी इन सभी लोगों को, इंस्टीटयूशंस को, industries को जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें नेशनल और global market provide की जा सके।

हम अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में semiconductor manufacturing research & development ecosystem यह सब करना चाहते हैं और इसी के लिए हम दिल्ली में semiconductor पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं ताकि दिल्ली में भी एक बेहतर infrastructure develop हो ताकि semiconductor industries यहां पर आके काम कर सकें। दिल्ली में हम अपने लिए एक दिल्ली drone policy लाएंगे क्योंकि दिल्ली में युवा बड़े उत्साहित हैं, उनके पास टैलेंट है और नई advance technologies, research और hi-tech manufacturing के माध्यम से हम दिल्ली में नई-नई सेक्टर में घुस करके काम करना चाहते हैं। दिल्ली बनाएगी भी, दिल्ली आगे बढ़ेगी भी यह सारे industrial sector के काम 160 करोड़ की लागत से जो मैंने पहले भी बताया कि हम confirming, non-confirming दोनों तरह के क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम industries में करेंगे ₹160 करोड़ सरकार इस साल देगी।

अध्यक्ष जी, विरासत और आधुनिकता का संगम हमारा टूरिज्म विभाग, शानदार काम किया पिछले एक साल में और इसीलिए हमने अपने इस विभाग का बजट बढ़ा के 121 करोड़ से 412 करोड़ रूपये कर दिया और अलग से art culture और language का 173 करोड़ कर दिया। दिल्ली की ब्रांडिंग, दिल्ली की positive image building इन सबके लिए सरकार काम करेगी। दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है 25 मार्च से आप सब आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा और दिल्ली को globally cultural map पर दिखाई देना चाहिए दिल्ली की एक ऐसी इमेज जो हमारी विकास और विरासत से जुड़ी हुई है उसे दिखाई देनी चाहिए। केवल monument देखने के लिए लोग यहां ना आएं, दिल्ली में एक्सपीरियंस उनका ऐसा होना चाहिए जो cleanliness से उनको यहां की सुंदरता से, यहां की ग्रीनरी से, यहां की infrastructure से, हर चीज को देखने में उनको आनंद आना चाहिए। हमने दिल्ली को साफ सुथरी और बेहतर दिल्ली करने के लिए टूरिज्म माध्यम से एक नया काम, काम पुराना है, दिक्कत पुरानी है पर एक नए स्वरूप में इस काम को करने की सोचा है, पूरी दिल्ली में एक हजार modern toilet block बनाए जाएंगे टूरिज्म विभाग के। टॉयलेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली में कोई व्यक्ति बाहर से आए या लोकल हो, वो एक समस्या घर से निकलने के बाद जो कहता है भाई toilet block बहुत खराब है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सफाई सब चीजें परेशान रहते हैं लोग विशेष रूप महिलाएं, महिलाएं दुखी रहती है कि भाई बाहर जा रहे हैं तो टॉयलेट कहां जाए? हम दिल्ली में एक हजार नए toilet block बनाएंगे और वो ऐसे होंगे जिसकी मेंटेनेंस पूरी तरीके से सरकार के खर्चे पर होगी, कोई उसमें एडवर्टाइजमेंट ये वो अलग-अलग तरह का compensation कुछ नहीं, सीधा-सीधा पैसे देके आपका toilet block साफ सुथरा मैनेज रहे, साफ सुथरा रहे, मेंटेंड रहे 24 घंटे खुला हो, जब जाते हैं लोग देखते हैं toilet block बंद है, नहीं, दिल्ली में शौचालयों को बेहतर करना इस बार हमने टूरिज्म को अलग से इस काम को

सौंपा है। दूसरी चीज दिल्ली की जितनी एंट्रीज हैं, जितने entry gate हैं, उन सबके beautification का काम हम टूरिज्म के माध्यम से दिल्ली में करने वाले हैं वह 13 entry gate उनको शानदार वेलकम गेट के रूप में बनाया जाएगा। दिल्ली जो inspiration है कवियों की, लेखकों की, कलाकारों की और हम देखते हैं इस दिल्ली शहर में सबके सदन है सब राज्यों के सदन यहां है, एक दिल्ली का ही सदन नहीं है। इस बार हम दिल्ली का सदन बनाएंगे भाई और उसके लिए हमने अलग से टूरिज्म विभाग को बजट दे दिया है। यह बढ़िया सा एक दिल्ली राज्य का अपना गेस्ट हाउस, एक सदन बनेगा जहां बाहर के अतिथि आकर रुकेंगे। एक बड़ा पुराना institution है दिल्ली में, Delhi Institute of Hotel Management & Catering, एक institution है बहुत पुराना है पर अब उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। हम इस इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करेंगे, इसको एंपावर करेंगे और हॉस्पिलैटिटी सेक्टर का एक बहुत ही रेनोल्ड इस इंस्टिट्यूशन को बना करके दिल्ली में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। जो काम हमारा टूरिज्म विभाग इसको लेके करेगा। दिल्ली में कॉन्सर्ट इकॉनमी डेवलप करनी है। इस दिशा में दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली की एक नई फिल्म पॉलिसी ताकि बाहर से लोग दिल्ली में शूटिंग के लिए अपने प्रोग्राम करने के लिए अपने कॉन्सर्ट करने के लिए प्रेरित हो और दिल्ली उन सब विधाओं के लिए पॉलिसी बनाएगी ताकि एंप्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, कल्चरल एक्सप्रेशन भी हो। ये सारी चीजें दिल्ली में जो आज तक नहीं हुई उन सबके लिए दिल्ली सरकार काम करेगी। एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो एक बिल्डिंग जिसका नाम टाउन हॉल है जिससे हममें से बहुत सारे लोगों का मन जुड़ा हुआ है। वर्षों से खंडर पड़ा हुआ है, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा। हमने केंद्र सरकार से बात करी है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम दिल्ली के टाउन हॉल को एक बहुत ही ग्लोबल हेरिटेज सेंटर बनाएंगे। जो सांस्कृतिक का केंद्र होगा, जो दिल्ली के हुनर को, दिल्ली के हार्ट को, दिल्ली के आर्ट को और दिल्ली के स्वाद को हर चीज का एक एग्जांपल बनता हुआ हम दिल्ली में टाउन हॉल को डेवलप करेंगे और एक बहुत ही रिच कल्चरल एक्सपीरियंस वहां पे लोगों को मिले। इसके लिए काम करेंगे। एक और सेक्टर है एवीजीसी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसका जिक्र किया है, देश की राजधानी है दिल्ली। हमारे युवाओं को हम इस नई दिशा में काम करने का मौका देंगे। इस इमर्जिंग इको सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज देंगे। हमारे जो युवा हैं वो क्रिएटर हैं, वो बहुत सारे युवा जो हैं अपने आप में उनके अंदर बहुत टैलेंट है। उन सबको दिल्ली का ब्रांड एंबेसडर बनाते हुए हम सपोर्ट करेंगे ताकि वो इस क्रिएटिव इकॉनमी में गेमिंग इंडस्ट्री में और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में अपना फ्यूचर बना सकें, अपना करियर बना सकें।

अध्यक्ष जी लगभग मैं समापन की ओर हूं। मैंने हर विभाग की बात करी। पर मैं फिर से उस बात पर आती हूं जहां से मैंने शुरू किया। दिल्ली के इस बजट को हमने ग्रीन बजट कहा है और ग्रीन बजट केवल कहने से नहीं होगा करने से होगा। दिल्ली में पर्यावरण, दिल्ली के वन क्षेत्र जो पिछली बार इसका बजट 505 करोड़ था। पर विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को हमारे विभाग को हमने इस बार 505 करोड़ से बढ़ा के 822 करोड़ रूपए का बजट दिया है। नए फॉरेस्ट एरिया डेवलप करेंगे, इंडीजीनियस प्लांट्स लगाएंगे। हमने अगले 4

साल के अंदर 35 लाख बड़े पेड़ जो कि भारतीय बीट के हैं। पीपल, आम, नीम ऐसे-ऐसे पेड़ जो सच में ऑक्सीजन गिवर हैं। हम ₹130 करोड़ का फंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। ₹44 करोड़ का फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं और दिल्ली के पार्क और गार्डन सोसाइटीज की डेवलपमेंट के लिए अलग से ₹25 करोड़ का फंड दे रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहती हूं कि हमारा ये जो बजट है वो दिल्ली के साथ कमिटमेंट है। ये दिल्ली का एनवायरमेंट हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और इस रिस्पांसिबिलिटी को हम गवर्नेंस के माध्यम से लगातार इस पे काम करेंगे। ग्रीन बजट को सुनिश्चित करते हुए हमने जितनी भी पॉलिसी बनाई उसमें हमने जनता को इनवॉल्व किया। इन डिसीजंस पे हर एक की सहमति ली और उस दिशा में काम करने के लिए पूरा एक साइंटिफिक रोड मैप बनाया है। हमने इस बार पॉल्यूशन कंट्रोल और इमरजेंसी मेजर्स करने के लिए अलग से ₹300 करोड़ का फंड रखा है। हमने दिल्ली नगर निगम को भी ₹2300 करोड़ की फंडिंग। दिल्ली में एमआरएस मशीनें, दिल्ली में लिटर पिककर लेने के लिए अलग से दिए हैं। हमने दिल्ली में मॉनिटरिंग सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए वॉर रूम बनाने के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए ₹2 करोड़ अलग से दिए हैं। अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं कि हमने वर्ल्ड बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशन पोल्यूशन पे हमें मिल पाएं। बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम हम डेवलप कर पाएं और दिल्ली धीरे-धीरे इस प्रदूषण की मार से बच पाए। हम कंक्रीट का जंगल नहीं बनाना चाहते दिल्ली को। हम हरियाली का आंगन बनाना चाहते हैं दिल्ली को और दिल्ली में अर्बन फॉरेस्ट पार्क, ग्रीन स्पेस के माध्यम से दिल्ली को फिर से ग्रीन दिल्ली बनाने की हमारी कमिटमेंट है। हमारी कमिटमेंट है अध्यक्ष जी और हम जानते हैं कि प्रकृति ही प्रगति की साथी है और प्रगति के लिए प्रगति के लिए प्रकृति को साथ में लेके चलना ही होगा। कूड़े के पहाड़ों की बात बार-बार आती है। हमने जो इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट डिस्पोजल का उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं हम। 7000 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी वेस्ट डिस्पोजल की दिल्ली की है उसको हम बढ़ा के 15000 मीट्रिक टन पर ले जाने के लिए नरेला, ओखला, गाजीपुर तेखंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का विस्तार करेंगे। हमने लीगेसी वेस्ट को खत्म करने के लिए लगातार लैंडफील्ड साइटों पर काम किया है और दिल्ली में जो काऊ डंग है, जो गोबर है, इसको वेस्ट टू वेल्थ के तरीके से यूज करने के लिए हम नए बायोगैस प्लांट लगाएंगे। लगभग रोजाना 1500 टन गोबर दिल्ली में होता है जो नालों के माध्यम से बह के यमुना जी में जाता है। यमुना को भी दूषित करता है, नालों की भी ब्लॉकेज होती है। परंतु अब दिल्ली में जितना भी ये काऊ डंग जनरेशन जो जनरेट हो रहा है, इसके लिए हम नए बायोगस प्लांट बनाएंगे ताकि उससे गैस बनाई जा सके जो हमारी दिल्ली को एक सर्कुलर इकोनमी मॉडल के रूप में काम आएगा और इसपे हम काम करेंगे और जब हम ईवी व्हीकल की बात करते हैं तो इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे-जैसे ईवी व्हीकल बढ़ेंगे वैसे-वैसे ई वेस्ट भी बढ़ेगा। तो दिल्ली में अभी से हम ई वेस्ट की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। ई वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्लांट बनाया जाएगा और उसपे लगातार सरकार काम कर रही है। इन सबको देखते हुए दिल्ली में कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन स्कीम को भी हम आगे लेकर के जा रहे हैं। एक निर्णायक मोड़ पर दिल्ली खड़ी है अध्यक्ष जी। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि हमने क्या-क्या किया, हम उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। हम इतना कह सकते हैं कि इस बजट की

हर पंक्ति सरकार की सोच तो है ही, सरकार की सोच तो है ही पर दिल्ली के जन-जन की आकांक्षाओं की गूंज भी हमारे इस बजट में शामिल है। और यह एक सामूहिक साधना है, यह साझा संकल्प है और इस संकल्प का परिणाम यही होगा कि हम लोग मिलकर के दिल्ली के लिए काम करें। मैं दिल्ली के करदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिनके परिश्रम की कमाई इस विकास की यात्रा की धुरी है। उन सभी नागरिकों का जिनके सुझावों से, जिनकी अपेक्षाओं से और विश्वास से हमने दिशा दी है इस बजट को। उन हजारों लोगों का, उन हजारों लोगों का जो कि लगातार अपने परामर्श से इस जन आंदोलन की प्रक्रिया में शामिल हुए। मैं अपने सभी अधिकारियों का, इन समर्पित अधिकारियों का, कर्मठ कर्मचारियों का, नीति निर्माताओं का और अपने सभी साथी मंत्रियों का, अपने सभी विधायकों का धन्यवाद देना चाहती हूं। जिनके विजन के साथ जो हमारे इस विजन के साथ लगातार काम कर रहे हैं और अपने काम को जन विश्वास के साथ जोड़ रहे हैं। दिल्ली की प्रगति को गति देने के लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूं जो लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दिल्ली सरकार को सपोर्ट भी करते हैं और केंद्र की अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और हमारे दिल्ली के माननीय एलजी महोदय जी का जिनका निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारी इस सरकार के लिए हमेशा लाभदायक रहा। 'सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया' इस भावना के साथ मैं दिल्ली के इस वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं[1] और आखिरी में दो लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि-

''दिल्ली की राहों में फिर से उजाला छाने लगा है
कि दिल्ली की राहों में फिर से उजाला छाने लगा है,
मेहनत का हर दीप अब जगमगाने लगा है,
मेहनत का हर दीप अब जगमगाने लगा है
नई उम्मीदों के संग कदम बढ़ाए हैं,
नई उम्मीदों के संग कदम बढ़ाए हैं,
हर अधूरे सपने को फिर से हमने सजाए हैं,
फिर से हमने सजाए हैं।''

भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम,वंदे मातरम।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सभी सभी अपना स्थान ले लें आगे की कारवाई अब माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026 -27 के लिए डिमांड फॉर ग्रांट पेश करेंगी ।

[1]दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23569 पर उपलब्ध।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री: इसी के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से राजकोशीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम लक्ष्य प्रतिबद्धताएं 2026-27 के प्रति भी सदन पटल पे प्रस्तुत करती हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इन अनुदान मांगों पर सदन में बजट पारित करने के लिए के दौरान विचार किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री वित्त मंत्री 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगी।

<u>अनुपूरक अनुदान मांगें (2025-26)</u>

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा और अंतिम भाग सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। जिसमें डिमांड नंबर एक लेजिसलेटिव असेंबली जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रूपए तथा कैपिटल में 10,75,000 रूपए हैं, कुल राशि 12,75,000 रूपए सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर एक पास हुई।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: डिमांड नंबर तीन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख हैं तथा कैपिटल में 2 लाख रूपए है, कुल राशि तीन लाख सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर तीन पास हुई।

डिमांड नंबर फोर फाइनेंस जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 26 करोड़ 36 लाख 80 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में 1 लाख रूपए हैं कुल राशि 1 अरब 26 करोड़ 37 लाख 80 हजार रूपए सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-4 पास

डिमांड नंबर-5 होम जिसमें रेवेन्यू में ₹1 लाख हैं तथा कैपिटल में 1 लाख रूपए कुल राशि दो लाख रूपए सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-5 पास हुई।

डिमांड नंबर'6 एजुकेशन जिसमें रेवेन्यू में 5 लाख रूपए हैं सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-6 पास हुई।

डिमांड नंबर-7 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ जिसमें रेवेन्यू में 4 लाख 60 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में 7 लाख रूपए कुल राशि 11 लाख 60 हजार रूपए सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-7 पास हुई

डिमांड नंबर-8 सोशल वेलफेयर जिसमें रेवेन्यू में 4 लाख रूपए हैं सदन रुपए सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर आठ पास हुई।

डिमांड नंबर-10 रेवेन्यू, जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 54 करोड़ 40 लाख 45 हजार रूपए है तथा कैपिटल में ₹ 21 लाख कुल राशि 1 अरब 54 करोड़ 61 लाख 65 हजार रुपए सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-10 पास हुई।

डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट जिसमें रेवेन्यू में 3 लाख रूपए हैं, सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-11 पास हुई।

डिमांड नंबर-12 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कैपिटल में 46 लाख दस हजार रूपए हैं सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर'-12 पास हुई।

डिमांड नंबर-15 विजिलेंस, जिसमें कैपिटल में 20 लाख रूपए हैं सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-15 पास हुई।

डिमांड नंबर-16 इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, जिसमें कैपिटल में 77 लाख 10 हजार रूपए हैं सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-16 पास हुई।

डिमांड नंबर-18 इलेक्शन जिसमें रेवेन्यू में ₹1 लाख हैं। सदन के सामने हैं।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-18 पास हुई।

डिमांड नंबर-19 प्लानिंग, जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 2 लाख रूपए कुल राशि 3 लाख रूपए सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-19 पास हुई।

बजट पास होने के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा लंच की व्यवस्था है। अच्छा बढ़िया लंच की।ठीक है ना। तो आवाज वैसे ही आनी चाहिए।

डिमांड नंबर-21, आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जिसमें रेवेन्यू में 4 लाख एक हजार रूपए है। सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-21 पास हुई।

डिमांड नंबर-22 ट्रांसपोर्ट जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 28 अरब 57 करोड़ 83 लाख रूपए हैं, कुल राशि 28 अरब 57 करोड़ 84 लाख रूपए है, सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-22 पास हुई।

डिमांड नंबर-24 टूरिज्म, जिसमें रेवेन्यू में ₹1 करोड़ 76 लाख रूपए है हैं। सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-24 पास हुई।

डिमांड नंबर-25 सिविल सप्लाई जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 49 करोड़ 65 लाख 50 हजार रूपए हैं सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-25 पास हुई।

डिमांड नंबर-26 डेवलपमेंट जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 1 लाख रूपए कुल राशि 2 लाख रूपए सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-26 पास हुई।

डिमांड नंबर-27 कोऑपरेटिव जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख हैं सदन के सामने सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-27 पास हुई।

डिमांड नंबर-28 इरीगेशन एंड फ्लड जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 12 लाख रूपए कुल राशि 13 रूपए लाख सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-28 पास हुई।

डिमांड नंबर-29 एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसमें कैपिटल में ₹15 करोड़ रूपए हैं, सदन के सामने हैं।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-29 पास हुई।

डिमांड नंबर-30 पब्लिक वर्क्स इसमें रेवेन्यू में 2 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 24 अरब 13 करोड़ 48 लाख रूपए हैं, कुल राशि 24 अरब 13 करोड़ 50 लाख रूपए सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर-30 पास हुई।

डिमांड नंबर 32, पावर जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रूपये हैं तथा कैपिटल में 1 लाख रूपये हैं, कुल राशि 2 लाख रूपये सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर 32 पास हुई।

सदन ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 4 अरब 32 करोड़ 53 लाख 36 हजार रूपये एवं कैपिटल में 52 अरब 88 करोड़ 32 लाख 95 हजार रूपये, कुल राशि 57 अरब 20 करोड़ 86 लाख 31 हजार रूपयों की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को मंजूरी दे दी है।

अब दा दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर- 02) बिल 2026, (बिल नंबर 06 ऑफ 2026), अब मुख्यमंत्री/ वित्त मंत्री दा दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर- 02) बिल 2026, (बिल नंबर 06 ऑफ 2026)को हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगी।

दिल्ली विनियोजन (संख्या -2) विधेयक 2026

श्रीमती रेखा गुप्ता (माननीया मुख्यमंत्री/ वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं 'दिल्ली विनियोजन (संख्या -2) विधेयक 2026, (2026 का विधेयक संख्या- 06) को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): मुख्यमंत्री/ वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री/ वित्त मंत्री जी बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता (माननीया मुख्यमंत्री/ वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं 'दिल्ली विनियोजन (संख्या -2) विधेयक 2026, (2026 का विधेयक संख्या- 06)को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूं।[2]

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खंड दो, खंड तीन व शेड्यूल बिल का अंग बने:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खंड दो, खंड तीन व शेड्यूल बिल का अंग बन गए।

[2] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23570 पर उपलब्ध।

प्रश्न है कि खंड एक, प्रीऐम्बल और टाइटल बिल का अंग बने:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खंड एक प्रीऐम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए।

अब मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि 'दा दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर-02) बिल, 2026 (बिल नंबर-06) ऑफ 2026) को पास किया जाए।

श्रीमती रेखा गुप्ता (माननीया मुख्यमंत्री/ वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि 'दिल्ली विनियोजन (संख्या -2) विधेयक 2026, (2026 का विधेयक संख्या- 06) को पास कर दिया जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

दा दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर- 02) बिल 2026, (बिल नंबर 06 ऑफ 2026) पास हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज सुबह सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले मेरे व्यक्तिगत मेल पर भी और दिल्ली विधानसभा की ईमेल पर भी कुछ आपत्तिजनक मेल प्राप्त हुई और यह विषय अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ा था। मैं सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ इस स्थिति पर उन्होंने निगरानी की, तुरंत पूरी जांच की गई। सभी सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के तुरंत जो है कार्रवाई की गई और सबसे खुशी की बात यह है कि सदन की कार्यवाही को हमने डिले नहीं होने दिया और यह सदन किसी भी इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से रुकने वाला नहीं है। यह इसी तरह निरंतर, सतत दिल्ली की सेवा में कार्यरत रहेगा और दिल्ली के लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान का यह केंद्र, यह लोकतंत्र का मंदिर निर्भीकता से अपने कार्य को पूरा करेगा।

अब सदन की कार्यवाही बुधवार 25 मार्च, 2026 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए....

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): अब तो बस एक ही शब्द रह गया था स्थगित, क्या कहना चाहते हो आप।

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): कार्यवाही बुधवार दिनांक यानी कल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 25 मार्च, 2026 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)